शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 14 अंक : 10 1 मई 2022

वैशाख - ज्येष्ठ मास, विक्रम संवत् 2079

संस्थापक
स्व. मुकुन्दराव कुलकर्णी

❖

परामर्श
के.नरहरि
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
जगदीश प्रसाद सिंघल
शिवानन्द सिन्दनकेरा

❖

सम्पादक
डॉ. राजेन्द्र शर्मा

❖

सह सम्पादक
डॉ. शिवशरण कौशिक
भरत शर्मा

❖

संपादक मंडल
प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय
डॉ. ओमप्रकाश पारीक
डॉ. एस.पी. सिंह

❖

प्रबन्ध सम्पादक
महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक
बजरंग प्रसाद मजेजी

❖

प्रेषण प्रभारी : **नौरंग सहाय**

❖

कार्यालय प्रभारी : **आलोक चतुर्वेदी**

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राजस्थान) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष : 8920959986

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

वार्षिक शुल्क ₹ 250/-
दस वर्षीय शुल्क ₹ 2000/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा चित्रों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में लघु उद्योगों की भूमिका

❑ **डॉ. राधेश्याम पी. चौधरी**

भारतीय अर्थव्यवस्था का आवश्यक घटक रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में रोजगार का सवाल उत्पादन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश के लिए इस क्षेत्र के विकास के बिना विकास करना मुश्किल है जो रोजगार योग्य है और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। रोजगार सृजन आर्थिक विकास का सबसे वांछनीय और आवश्यक परिणाम होना चाहिए। क्योंकि यह अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है। किसी देश में आम लोगों की आर्थिक भलाई के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है।

4

अनुक्रम

3.	सम्पादकीय	- डॉ. राजेन्द्र शर्मा
8.	भारत में कोविड-19 प्रबंधन व अर्थव्यवस्था	- प्रो. राजेश जाँगिड़
10.	भारत में कोरोना प्रबंधन : चुनौती एवं अवसर	- डॉ. केशव शर्मा
15.	कोरोना का प्रभाव व भारतीय अर्थव्यवस्था	- उपेंद्र सिंह
19.	कोरोना वायरस व आर्थिक प्रभाव	- डॉ. रेनू यादव
21.	कोरोना का प्रभाव और भारतीय अर्थव्यवस्था	- डॉ. अनूप कुमार आत्रेय
23.	भारतीय अर्थव्यवस्था : गौरवशाली अतीत से	- मनोज भारी
25.	ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव : एक...	- डॉ. सुधीर कुमार श्रीवास्तव
28.	आत्मनिर्भरता में बचत की भूमिका	- प्रो. अश्विनी महाजन
30.	सबका साथ सबका विकास की अवधारणा	- डॉ. ईश्वर चन्द्र शर्मा
32.	Sabaka Sath Sabaka Vikas : A Mission ...	- Dr. Smita R. Deshmukh
38.	Shades of Economic Crises in Grip of ...	- Dr. Suneel Kumar
41.	COVID-19 and Indian Economy : Aftermath..	- Dr. Meenu Maheshwari

Impact of Vaccination on Economy

❑ **Dr. Babita Solanki**

Vaccines can help end recessions under the right circumstances. Enough people must be willing to get vaccinated to achieve herd immunity, and once that level is reached, businesses and consumers must return to prior levels of economic activity. Journey of vaccination has impacted on the economy positively uptill now. So we can say that these jabs are not only for human life but also for economy.

35

संपादकीय

डॉ. राजेन्द्र शर्मा
सम्पादक

कोविड-19 महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछले दो वर्ष कठिनाई भरे रहे हैं। इस दौरान कई सारे उद्योग-धंधे बंद हुए, उत्पादन में गिरावट आई, वैश्विक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, लोगों का रोजगार चला गया तथा आर्थिक असमानता और गरीबी दोनों में वृद्धि हुई है। यद्यपि इस मुश्किल समय में भी कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में सशक्त भूमिका निभाई है। कृषि ने देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय माँग को भी पूरा किया है। कोरोना महामारी और उसके परिणाम स्वरूप लॉकडाउन से पूरी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद कृषि क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। यह वृद्धि 2021-22 में बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गई। अब तो सरकार इस क्षेत्र में कृषि ड्रोन्स (यूएवी - मानव रहित वायुमार्ग वाहन) का प्रयोग करने जा रही हैं। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी और भूजल की हो रही बर्बादी को देखते हुए गंगा नदी के किनारे पाँच किलोमीटर चौड़े गलियारे वाले खेतों में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सभी सकारात्मक तथ्यों के बावजूद यह प्रश्न विचारणीय है कि आज भी देश को अपनी घरेलू माँग को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का आयात क्यों करना पड़ रहा है तथा क्यों देश के कुल बुवाई क्षेत्र में से सिर्फ आधे क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं?

भारतीय अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र का है। यह सेवा क्षेत्र कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों की वजह से सबसे बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। पर अब विभिन्न संकेतक सेवा क्षेत्र में हुए सुधारों को दर्शा रहे हैं। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में इस क्षेत्र की विकास दर 8.2 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई है।

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में महामारी से प्रेरित मंदी से उबरने के बाद स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैश्विक आपूर्ति बाधाओं और रूस-यूक्रेन संघर्ष की चुनौतियों के बावजूद भारत के उत्पाद और सेवाओं का निर्यात ऐतिहासिक स्तर पर पहुँचा है। भारत ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सभी छोटे-बड़े देशों की भरपूर सहायता एवं सहयोग किया है। वहीं, अधिकांश देशों में चीन के प्रति संदेह गहराता गया है। देश में कॉरपोरेट कर की दर घटने, ढाँचागत व्यवस्था में सुधार होने, एमएसएमई को नए सिरे से परिभाषित करने तथा इज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा होने का लाभ निर्यात क्षेत्र को मिला है। इन्हीं सब वजहों से एवं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों एवं सेवाओं के बल पर देश ने निर्यात में नया रिकार्ड बनाया है। अब तो हम दुनिया के प्रमुख खाद्यान्न निर्यातक देश के रूप में उभर रहे हैं। निजी कारोबारी तो विद्यमान वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया के विभिन्न देशों को गेहूँ का निर्यात करने के लिए पंजाब-हरियाणा के किसानों से बेहतर दामों पर अधिक से अधिक गेहूँ खरीद रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था पारंपरिक तौर पर नकदी पर निर्भर रही है। लेकिन नोटबंदी और उसके पश्चात कोरोना के समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से लेन-देन में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। मुद्रा के जरिए लेन-देन से संक्रमण की सम्भावना थी। इस संभावना को समाप्त करने के लिए स्पर्श रहित लेन-देन जन-जन तक पहुँच गया। प्राय: सभी व्यवसायों ने लॉकडाउन से निबटने और उबरने के लिए डिजिटल सेवाओं या एप्लीकेशनों को भरपूर अपनाया।

आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता और अमरीका एवं चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक एवं स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है। फिनटेक (फाइनैंशियल टेक्नोलॉजी) का तात्पर्य है - वित्त और प्रौद्योगिकी का समन्वय। फिनटेक उद्योग से न केवल अर्थव्यवस्था का काम करने का तरीका बदल रहा है अपितु कारोबार के नए मार्ग भी खुल रहे हैं। नकदरहित भुगतान से लेकर क्राउड फंडिंग और वर्चुअल करेंसी तक, सब फिनटेक की ही देन हैं। अब यह बीते जमाने की बात हो गयी जब किसी को रकम भेजने के लिए बैंक में जाकर लाइन में लगना पड़ता था। अब यह काम यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) या बैंक एप्लिकेशन के माध्यम से चुटकियों में घर बैठे ही हो जाता है। फिनटेक उद्योग जीवन को सुविधाजनक बनाने के साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी दे रहा है।

भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी एवं सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पर यदि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखा जाए तो हम 140 वें पायदान पर हैं। ऐसे में कोविड के दुष्प्रभावों से उबरते हुए अहम् प्राथमिकता है - अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाना। इस हेतु अवसंरचना का परिमाणात्मक विस्तार एवं गुणात्मक विकास, पूँजीगत व्यय में वृद्धि, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कल्याणकारी कार्यक्रमों को बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा किए जाने पर ही भारत अपनी अर्थव्यवस्था को 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को यथासमय प्राप्त कर सकेगा। ❑

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में लघु उद्योगों की भूमिका

डॉ. राधेश्याम पी. चौधरी
सहयोगी प्राध्यापक-वाणिज्य विभाग,
शिवरामजी मोघे कला, वाणिज्य व
विज्ञान, केळापूर (पांढरकवडा)
जि. यवतमाळ (महाराष्ट्र)

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, जिसकी जनसंख्या विश्व में दूसरी सबसे बड़ी है। कृषि के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में सबसे अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है। इससे पता चलता है कि कृषि के बाद अधिकांश भारतीय अपनी आजीविका के लिए लघु उद्योगों पर निर्भर हैं। यद्यपि इन उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में कम पूंजी, श्रम, स्थान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, लेकिन रोजगार सृजन, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, निर्यात योग्य उत्पादों के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान अद्वितीय है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सहयोग, रियायतें और प्रोत्साहन की नीति अपनाई है। देश के आर्थिक विकास में भी इस उद्योग-क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जीवित रखने और विकसित करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता एसएमई क्षेत्र की तीव्र वृद्धि है। 1948 और 1956 की भारत की औद्योगिक नीति ने इसे लघु उद्योगों में लघु पूंजी निवेश में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में एक विशेष भूमिका सौंपी। 1977 में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए गए। इस लेख में भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र के महत्व को समझाने की कोशिश की है। इस लेख में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करने के मामले में लघु उद्योग के महत्व को दिखाने की कोशिश की है।

प्रस्तावना

20वीं सदी की शुरुआत से दुनिया के कई देशों ने औद्योगीकरण को अपनाया है। लेकिन उससे पहले भारत के बड़े शहरों में बड़े पैमाने मे लघुउद्योग और गृह उद्योग चल रहे थे। भारत में बने वस्त्र, हस्तशिल्प और आभूषण की मांग पूरी दुनिया में थी। आजादी के बाद भारत जैसे विकासशील देश को औद्योगीकरण की सख्त जरूरत थी। भारत को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और जनशक्ति का पर्याप्त और कुशल उपयोग करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए औद्योगीकरण की आवश्यकता थी। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, देश को निर्माण में आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए भारत सरकार ने भारत के औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न औद्योगिक नीतियों की घोषणा की। 1991

में, भारत सरकार ने बदलती वैश्विक स्थिति के अनुकूल एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इन सभी औद्योगिक नीतियों में भारत सरकार ने लघु उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और न केवल इस क्षेत्र के माध्यम से रोजगार प्रदान करते हैं बल्कि लघु उद्योगों को भी माल के निर्माण और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में देखा जाता है। कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर चलाया जाता है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग भारत के तीव्र आर्थिक विकास में सबसे आगे हैं। स्वतंत्रता के बाद की अवधि के बाद से एसएमई क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने रोजगार वृद्धि और आर्थिक विकास के मामले में बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना उच्च विकास दर हासिल की है। 1950 में पंजीकृत लघु इकाइयों की संख्या 16000 थी, 1961 में यह बढ़कर 36000 और 2000-01 में 33.7 लाख हो गई। पिछले दो दशकों में, लघु उद्योगों ने साधारण उपभोक्ता वस्तुओं से आधुनिक सिंथेटिक उत्पादों की ओर प्रगति की है। उदा. इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण के तरीके, माइक्रोवेव घटक, टीवी। आदि। सरकार ने लघु उद्योगों के लिए कुछ भंडार की नीति अपनाई है। 1972 में लघु उद्योगों के लिए 177 वस्तुएँ आरक्षित की गईं। 1983 में, इन भंडारों की संख्या बढ़कर 837 हो गई। लघु उद्योगों द्वारा लगभग 7500 वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यह न केवल रोजगार पैदा करता है बल्कि अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र के महत्व का अध्ययन करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र के योगदान का अध्ययन करना। लघु उद्योगों में रोजगार का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र का महत्व

आज, एक बड़े देश का आर्थिक और सामाजिक विकास बड़े वाणिज्यिक कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का एक विशेष स्थान और महत्व है। इसका कारण यह है कि भारत जैसी सबसे बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करने की क्षमता कृषि के बाद के छोटे पैमाने के क्षेत्र में निहित है। नतीजतन, एसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में, भारत की आर्थिक मुक्ति लघु और कुटीर उद्योगों में निहित है। योजना आयोग के अनुसार कुटीर और लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें कभी भी नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता है। लघु उद्योगों का महत्व निम्नलिखित दृष्टि से देश के विकास के लिए उपयोगी माना जाता है साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एसएमई का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का आवश्यक घटक रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में रोजगार का सवाल उत्पादन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश के लिए इस क्षेत्र के विकास के बिना विकास करना मुश्किल है जो रोजगार योग्य है और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। रोजगार सृजन आर्थिक विकास का सबसे वांछनीय और आवश्यक परिणाम होना चाहिए। क्योंकि यह अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है। किसी देश में आम लोगों की आर्थिक भलाई के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है।

1. अधिकतम रोजगार के अवसर: लघु उद्योगों में रोजगार उपलब्ध होने की अधिक संभावना है। उनके विकास और प्रोत्साहन से देश में बेरोजगारी की मौजूदा समस्या को कुछ हद तक हल किया जा सकता है। चूंकि लघु और कुटीर उद्योग श्रम प्रधान हैं, इसलिए इन उद्योगों को कम पूंजी निवेश के साथ विकसित करके अधिक रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। यह भारत जैसे विकासशील और कृषि प्रधान देश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

2. पूंजी की समस्या का समाधान : चूंकि कुटीर और लघु उद्योग श्रम प्रधान हैं, ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। एक अनुमान के अनुसार बड़े पैमाने के उद्योगों में एक करोड़ की पूंजी निवेश करके केवल 35 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, जबकि लघु उद्योगों में एक ही पूंजी से लगभग 3000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इसीलिए लघु उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है।

3. राष्ट्रीय आय का समान वितरण : इन उद्योगों के माध्यम से राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश का समान वितरण संभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन उद्योगों का स्वामित्व अधिक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में है। यह आर्थिक शक्ति को केंद्रीकृत नहीं करता है। इसके अलावा, कम उत्पादकता के कारण, इन उद्योगों में श्रमिकों के शोषण की संभावना कम होती है। इस प्रकार, राष्ट्रीय आय के समान वितरण की संभावना है।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल : भारत एक कृषि प्रधान देश है, और अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, लेकिन हमारे देश में

किसानों को साल भर रोजगार नहीं मिलता है। अर्ध-बेरोजगारी की समस्या का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। इस समस्या को हल करने में छोटे व्यवसाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, इन उद्योगों को हमारे देश में विकसित करने की आवश्यकता है।

5. औद्योगिक विकेंद्रीकरण : लघु उद्योगों के विकास ने देश में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में मदद की है। इससे पूंजी का विकेंद्रीकरण होता है और आय और धन का समान वितरण होता है। दूसरे शब्दों में, इन उद्योगों की स्थापना से आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है। इतना ही नहीं, विकेंद्रीकरण सभी औद्योगिक बुराइयों को समाप्त करता है, इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि इन उद्योगों के विकास से देश के सभी लोगों को लाभ होता है। यही उसकी विशेषता है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक मूल्यवर्धन में एसएमई क्षेत्र का योगदान कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत होने का अनुमान है। एक छोटे से क्षेत्र में अचल संपत्तियों में 10 लाख रुपये का निवेश रुपये की वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करता है। लघु व्यवसाय क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। विभिन्न नियोजन अवधियों में विकास दर बहुत प्रभावी रही है। छोटी इकाइयों की संख्या 1980-81 में 0.87 मिलियन से बढ़कर 2000 में 3 मिलियन छोटी इकाई हो गई है। जब इस क्षेत्र के प्रदर्शन की तुलना पूरे विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र के विकास से की जाती है, तो एसएमई क्षेत्र के लचीलेपन में विश्वास होता है।

लघु उद्योगों में रोजगार संबंधी योगदान

भारत में लघु उद्योग कृषि के बाद भारतीय आबादी के लिए सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। यह अनुमान है कि एक छोटे से क्षेत्र में अचल संपत्तियों में 100,000 रुपये का निवेश करने से चार लोगों के लिए रोजगार पैदा होता है। रोजगार सृजन-समूहवार उद्योग खाद्य उत्पाद उद्योग रोजगार सृजन में पहले स्थान पर है, जिसमें 0.48 मिलियन (13.1 प्रतिशत) लोग कार्यरत हैं। अगले दो उद्योग समूह गैर-धातु खनिज उत्पाद हैं जिनमें 0.45 मिलियन (12.2 प्रतिशत) रोजगार और 0.37 मिलियन (10.2 प्रतिशत) रोजगार वाले धातु उत्पाद हैं। रसायन और रासायनिक उत्पाद, मशीनरी के पुर्जे, बिजली के पुर्जे, लकड़ी के उत्पाद, बुनियादी धातु उद्योग, कागज उत्पाद और छपाई, होजरी और रेडीमेड वस्त्र, मरम्मत सेवाएँ और रबर तथा प्लास्टिक उत्पादों को छोड़कर कुल योगदान का 9 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। इन आठ उद्योग समूहों में से 49 प्रतिशत।

प्रति यूनिट रोजगार

पेय, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों में लगी इकाइयों में प्रति इकाई रोजगार उच्चतम (20) था। इसका मुख्य कारण इस उद्योग में विशेष रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम और तमिलनाडु में रोजगार की उच्च संभावना है। इसके बाद सूती वस्त्र उत्पाद (17), गैर-धातु खनिज उत्पाद (14.1), बुनियादी धातुकर्म उद्योग (13.6) और विद्युत मशीनरी और पुर्जे (11.2) हैं। सबसे कम संख्या 2.4 मरम्मत सेवा क्षेत्र में है। प्रति इकाई रोजगार महानगरीय क्षेत्रों में उच्चतम (10) और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम (5) था। हालांकि, रासायनिक पदार्थों और रासायनिक उत्पादों, गैर-धातु उत्पादों और बुनियादी धातु उद्योगों में प्रति इकाई रोजगार दर महानगरीय/शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी। शीतल पेय, तंबाकू उत्पाद (31 व्यक्ति), सूती वस्त्र उत्पाद (18), बुनियादी धातुकर्म उद्योग (13) और गैर-धातु खनिज उत्पाद (12) में शहरी क्षेत्रों में प्रति इकाई रोजगार सबसे अधिक है।

स्थानवार रोजगार वितरण

ग्रामीण

ग्रामीण रोजगार में गैर-धातु उत्पादों की हिस्सेदारी 22.7 प्रतिशत है। खाद्य उत्पादों में 21.1 प्रतिशत, लकड़ी के उत्पादों और रसायनों और रासायनिक उत्पादों में 17.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।

शहरी

शहरी क्षेत्रों के लिए, खाद्य उत्पादों और धातु उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 22.8 प्रतिशत है। मशीनरी घटक, गैर-धातु खनिज उत्पाद और रसायन और रासायनिक उत्पाद, बिजली को छोड़कर, कुल रोजगार का 26.2 प्रतिशत हिस्सा था। धातु उत्पादों, मशीनरी और भागों, बिजली और कागज उत्पादों और छपाई (कुल मिलाकर 33.6 प्रतिशत) को छोड़कर महानगरीय क्षेत्र में प्रमुख उद्योग थे।

राज्यवार रोजगार वितरण

तमिलनाडु (14.5 प्रतिशत) रोजगार

वर्ष	वृद्धि	दर	लक्ष्य(लाख)	उपलब्धता (लाख)
1992-93	128.0	134.06	3.28	1 m
1993-94	133.0	139.38	3.28	S
1994-95	138.6	146.56	5.15	G WW
1995-96	144.4	152.61	4.13	
1996-97	150.5	160.00	4.88	
1997-98	165.0	167.20	4.50	
1998-99	170.1	171.58	2.61	
1999-00	175.4	177.3	3.33	

में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। इसके बाद महाराष्ट्र (9.7 फीसदी), उत्तर प्रदेश (9.5 फीसदी) और पश्चिम बंगाल (8.5 फीसदी) का नंबर आता है। गुजरात (7.6 फीसदी), आंध्र प्रदेश (7.5 फीसदी), कर्नाटक (6.7 फीसदी) और पंजाब (5.6 फीसदी) ने मिलकर 27.4 फीसदी का योगदान दिया। नागालैंड, सिक्किम और दादरा और नगर हवेली में प्रति यूनिट रोजगार क्रमशः 17, 16 और 14 था। वह महाराष्ट्र, त्रिपुरा और दिल्ली में 12 साल की थीं। सबसे कम संख्या मध्य प्रदेश में 2 थी। अन्य सभी मामलों में यह औसतन लगभग 6 था।

निर्यात

एसएमई क्षेत्र भारत के वर्तमान निर्यात प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लघु व्यवसाय क्षेत्र का भारतीय निर्यात में 45 से 50 प्रतिशत का योगदान है। कुल निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत सीधे लघु उद्योगों से होता है। प्रत्यक्ष निर्यात के अलावा, छोटे उद्योगों का अप्रत्यक्ष निर्यात में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान है। यह काम मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, मर्चेंट हाउसेज और एक्सपोर्ट हाउसेज के जरिए किया जाता है। वे बड़ी इकाइयों से निर्यात ऑर्डर के रूप में या तैयार-से-निर्यात माल में उपयोग के लिए भागों और भागों के उत्पादों के रूप में भी हो सकते हैं। कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे क्षेत्र के निर्यात में गैर-पारंपरिक उत्पाद शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था का आवश्यक घटक रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में रोजगार का सवाल उत्पादन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश के लिए इस क्षेत्र के विकास के बिना विकास करना मुश्किल है जो रोजगार योग्य है और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। रोजगार सृजन आर्थिक विकास का सबसे वांछनीय और आवश्यक परिणाम होना चाहिए। क्योंकि यह अधिक लोगों को रोजगार

प्रदान करता है और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है। किसी देश में आम लोगों की आर्थिक भलाई के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। बेरोजगार आर्थिक विकास (रोजगार विहीन विकास) न केवल राष्ट्र की नजर में व्यर्थ है बल्कि देश के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में रोजगार सृजन पहला समावेशी कारक है। इसलिए, आर्थिक विकास से पर्याप्त रोजगार सृजन होना चाहिए। राष्ट्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ कृषि श्रमिकों की संख्या कम की जानी चाहिए और उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजित किए जाने चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक रोजगार सृजित हों और बड़े व्यवसाय स्थापित हों। लेकिन आर्थिक विकास के समग्र अनुभव के साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि पैंसठ वर्षों के विकास के बाद भी हमारे देश के कुल श्रमिकों में से केवल 2.3 प्रतिशत ही ऐसे उद्योगों को शामिल कर पाए हैं। इसका मतलब है कि बड़े उद्यम अपने निवेश की गई राशि के अनुपात में रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं। अन्य विकसित देशों में बड़े उद्योगों में रोजगार के बारे में भी यही सच है। उदाहरण के लिए, चीन 9.7 प्रतिशत है, संयुक्त राज्य अमेरिका 8 प्रतिशत है और इंग्लैंड लगभग 9 प्रतिशत है।

हमारे देश में श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 48 करोड़ है। इसमें से लगभग 26 करोड़ कृषि में हैं और शेष 22 करोड़ में से आठ करोड़ गैर-कृषि क्षेत्र में हैं। इनमें से केवल 2.3 बड़े पैमाने के उद्योगों में कार्यरत हैं। इसका मतलब यह है कि अधिकांश गैर-कृषि श्रमिकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा नियोजित किया जाता है, इसके बाद लघु उद्योगों का स्थान आता है।

निर्यात क्षेत्र में सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों का प्रदर्शन भी सराहनीय है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देश की कुल विदेशी मुद्रा आय में लघु उद्योगों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत इसी क्षेत्र में है। 2000 से 2005 तक के पाँच वर्षों में, सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) ने अपने कुल उत्पादन का क्रमशः 26, 25, 27, 27 और 30 प्रतिशत निर्यात करके विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका मतलब है कि भारतीय एसएमई क्षेत्र में विदेशी मुद्रा उत्पन्न करने के साथ-साथ भारतीय आबादी को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है और इस क्षेत्र को और विकसित करने की आवश्यकता है। ❑

भारत में कोविड-19 प्रबंधन व अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान

प्रो. राजेश जाँगिड़
आचार्य,
आर्थिक अध्ययन विभाग
केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
पंजाब

कोविड-19 के दौरान पिछले 2 वर्षों से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पूर्ति पक्ष से समस्याओं के साथ-साथ माँग पक्ष और मुद्रास्फीति के कारण अनिश्चितता से ग्रसित रही। सैकड़ों वर्षों के पश्चात आने वाली ऐसी महामारी के प्रबंधन के संबंध में भारत द्वारा विकास के पुनरुद्धार की गति के साथ-साथ आर्थिक सूचकों का मूल्यांकन करना महत्त्वपूर्ण है। महामारी के प्रथम दौर की अवधि अर्थव्यवस्था के लिए अधिक घातक रही व दूसरे दौर की अवधि अर्थव्यवस्था के लिए कम घातक रही लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक घातक रही। वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9 प्रतिशत दर्ज की गई इसका तात्पर्य है कि 2019-20 के पूर्व कोविड-19 के स्तर को अर्थव्यवस्था ने पार कर लिया है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार प्रभाव को देखने पर ज्ञात होता है कि पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र सबसे कम प्रभावित रहा। 2019-20 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत थी जो 2020-21 में 3.6 प्रतिशत रही। खाद्यान्न फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र बढ़ा साथ ही खाद्यान्न उत्पादन 150 मिलियन टन के उच्च स्तर पर पहुँच गया। यह वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि के लिए अच्छा संकेत है। औद्योगिक क्षेत्र जो 2020-21 में 7 प्रतिशत से नीचे गिरा था 2021-22 में 11.8 प्रतिशत से विस्तार कर महामारी से पूर्व के स्तर से आगे निकल गया है। सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में बढ़ते निवेश तथा गृह निर्माण के क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों के कारण स्टील और सीमेंट का उपभोग स्तर महामारी के पूर्व के स्तर को पार कर गया है। सेवा क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है, कि वृद्धि दर 2020-21 में 8.4 प्रतिशत की कमी देखी गई 2021-22 में 8.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और अवसंरचना क्षेत्र पर सरकार के बढ़ते खर्च के कारण अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में निवेश जीडीपी अनुपात 29.6 प्रतिशत हो गया है जो पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक है। वर्ष 2021-22 में निवेश में 15 प्रतिशत की वृद्धि यह इंगित करती है कि निवेश महामारी पूर्व के स्तर से ऊपर आ गया है। वर्ष 2021-22 में निर्यात में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि तथा आयात में 29.4 प्रतिशत की वृद्धि ने महामारी से पूर्व के स्तर को पार कर लिया है।

वायरस के बदलते रूपों के कारण महामारी की अनेक दौर व आपूर्ति शृंखला की समस्या नीति निर्माताओं के लिए चुनौतिपूर्ण रही। इन कठिनाई की परिस्थिति में भारत सरकार ने इस तरह की रणनीति का चुनाव किया जिसके तहत कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा जाल का गठन किया गया साथ ही अद्यतन सूचना के आधार पर लचीली रणनीति अपनाई गई जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचकांकों की

जानकारी के आधार पर अनिश्चितता से निबटने के लिए प्रयास किए गए। इस प्रकार की रियल टाइम डाटा संग्रह के आधार पर लचीली व प्रतिक्रियावादी सुधार रणनीति से विकास में सहायता मिलती है। 2020-21 में सरकार ने शुरू में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने और लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नकदी प्रदान करने जैसे उपाय अपनाये। इसके पश्चात विशिष्ट चुनौतियों पर लक्षित नियमित घोषणाओं के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। दुनिया के सबसे बड़े निशुल्क भोजन कार्यक्रम, छोटे व्यवसायियों के लिए राहत सहायता, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ ही व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी से वृद्धि देखी गई।

कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो सुरक्षा जाल गठित किया गया उसके अंतर्गत नकद सहायता, खाद्य सुरक्षा, रोजगार के अवसरों का सृजन, द्रुतगति से ग्रामीण व शहरी आवास निर्माण, कौशल विकास व ऋण उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनवरी 2022 तक सरकार ने 156 करोड से अधिक कोविड-19 टीकाकरण की खुराक की व्यवस्था कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 15 से 18 आयु वर्ग के लिए तथा 12 से 15 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण का सफलतापूर्वक संचालन महामारी को रोकने की दिशा में अद्वितीय तत्परता को दर्शाता है। समष्टि आर्थिक सूचकांक अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुत्थान को दर्शाते हैं। पिछले 2 वर्षों में अनुकूल भुगतान संतुलन, 634 अरब अमेरिकी डालर का विदेशी मुद्रा भंडार जो विश्व का सबसे चौथा बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार था व बढ़ता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थव्यवस्था को विदेशी क्षेत्र में बेहतर समायोजन के अवसर प्रदान कर रहा है। सरकारी राजस्व में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार तथा मुद्रास्फीति की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है (आर्थिक समीक्षा, 2021-22, भारत सरकार)।

पूर्ति पक्ष में सुधार

महामारी के खिलाफ आर्थिक प्रतिक्रिया की विशिष्ट विशेषता माँग पक्षीय प्रबंधन पर पूर्ण निर्भरता की अपेक्षा पूर्ति पक्षीय सुधारों पर बल देना रहा है। इन सुधारों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का सरलीकरण, निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन व कई क्षेत्रों में विनियमन सम्मिलित है। पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि माँग पक्ष को बढ़ाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष व बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाता है। पूर्ति पक्ष के सुधारों में दो सामान्य विषय सम्मिलित हैं। प्रथम के अंतर्गत महामारी के बाद दुनिया में उत्पन्न अनिश्चितता से निपटने के लिए लचीलापन और नवाचार में सुधार हेतु उपाय सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत साधन बाजार सुधार सम्मिलित हैं जैसे प्रक्रिया सुधार, निजीकरण, बुनियादी ढाँचे का निर्माण, अंतरिक्ष, द्रोण व स्थानिक मानचित्रण सम्मिलित है। दूसरे प्रकार के सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन लाने के उद्देश्य से किये सुधार हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक अवसंरचना का निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रावधान, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रमुख उद्योगों का समर्थन व विदेशी व्यापार समझौते आदि सम्मिलित है। पूर्ति पक्ष से सुधारों में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सुधार, बीपीओ क्षेत्र संबंधी सुधार, दूरसंचार क्षेत्र संबंधी सुधार, सार्वजनिक खरीद नीति, विमानन, वित्तीय क्षेत्र, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग क्षेत्र में सुधार, अंतरिक्ष व्यवस्था ने क्षेत्र में सुधार, विनिवेश, श्रम सुधार व रक्षा क्षेत्र के सुधार सम्मिलित हैं।

वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर में कमी देखी गई। साथ ही वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.2 प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान तथा वर्ष 2022-23 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 8 से 8.5 प्रतिशत के बढ़ने का है। बेहतर वैक्सीन कवरेज, आपूर्ति पक्ष के सुधार, लाभ और नियमों में ढील, मजबूत निर्यात वृद्धि और पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए राजकोषीय उपलब्धता ने वर्ष 2022-23 की वृद्धि दर को समर्थन किया है।

वृद्धि दर

वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर में कमी देखी गई। साथ ही वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.2 प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान तथा वर्ष 2022-23 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 8 से 8.5 प्रतिशत के बढ़ने का है। बेहतर वैक्सीन कवरेज, आपूर्ति पक्ष के सुधार, लाभ और नियमों में ढील, मजबूत निर्यात वृद्धि और पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए राजकोषीय उपलब्धता ने वर्ष 2022-23 की वृद्धि दर को समर्थन किया है। विश्व बैंक में एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2022-23 व 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 और 2022-23 में 9 प्रतिशत रहने का अनुमान है साथ ही अनुमान दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2023-24 में 7.31 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। इन 3 वर्षों की वृद्धि दर के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में प्रदर्शन कर रहा है। ❑

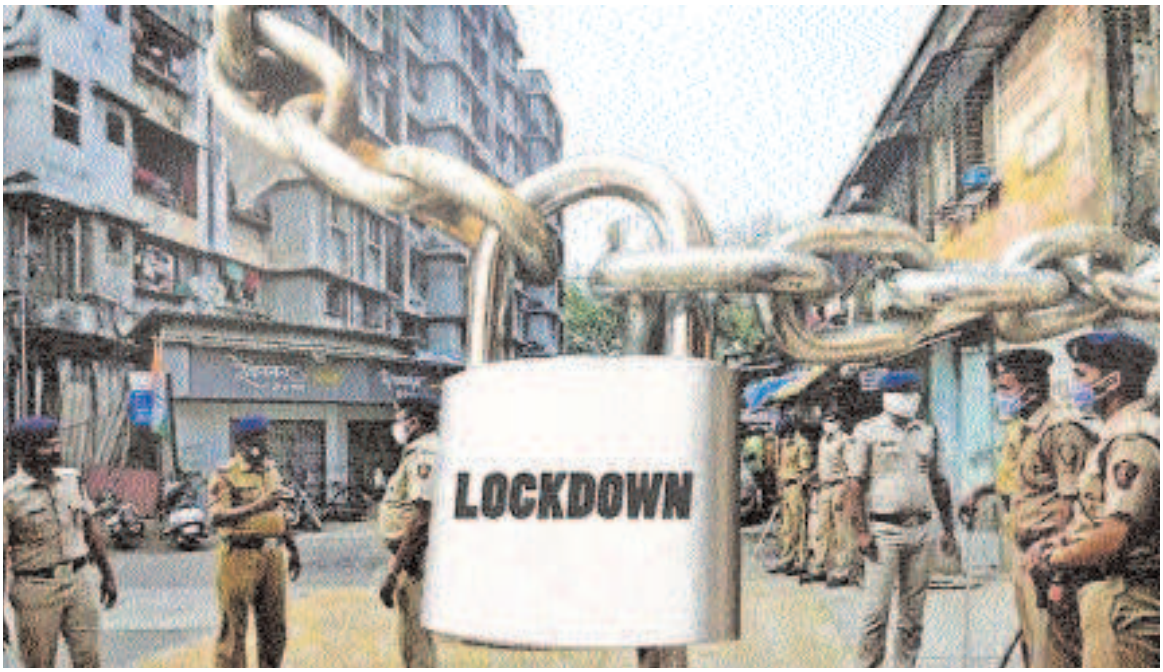

भारत में कोरोना प्रबंधन : चुनौती एवं अवसर

डॉ. केशव शर्मा
सह आचार्य, गणित,
राजकीय महाविद्यालय बेगूं,
चित्तौड़ (राज.)

जब चाइना में दिसंबर 2019 में कोरोना कोविड-19 का प्रथम केस सामने आया तो विश्व भर के वैज्ञानिकों ने, विश्व के सभी प्रकार के मीडिया चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ने इस घटना को बहुत प्रचारित किया जैसे कि उन्हें पता हो कि यह बीमारी कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। अब चाहे यह इन सब की साठगाँठ हो अथवा कुछ और। यहाँ तक कि जब मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया, तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह वायरस कोई प्राकृतिक वायरस नहीं होकर प्रयोगशाला जनित वायरस है तथा इस वायरस को बनाने वाला चाइना है। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है यह भविष्य में होने वाली जाँचों से ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के कुशल वैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों की सलाह से सभी देशवासियों को इस बीमारी के खतरनाक होने के बारे में अवगत करा दिया था। हम सभी जानते हैं कि किस

प्रकार प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2020 में एक अलग प्रकार का कर्फ्यू लगाया जिसे उन्होंने 'जनता कर्फ्यू' का नाम दिया, जो कि एक प्रकार से नागरिकों के द्वारा स्वप्रेरित कर्फ्यू था और किस प्रकार संपूर्ण भारतीय जनमानस उनके इस आह्वान को आदेश मानकर 24 घंटे के लिए घर के अंदर सीमित हो गए। यह स्वप्रेरणा वाला कर्फ्यू आने वाले लॉकडाउन का संकेत मात्र था। इन परिस्थितियों में अधिकांश भारतीय जनमानस ने प्रधानमंत्री जी की बात को इस प्रकार महत्व दिया जैसे कि घर के मुखिया की बात को पूरा परिवार महत्त्व देता है अर्थात् इन विकट परिस्थितियों में भारतीय जनमानस अपनी संस्कृति एवं विचार, कि घर के मुखिया को महत्त्व दिया जाना है, का अक्षरशः पालन किया। पूरा देश एक परिवार की तरह व्यवहार करने लगा। इस प्रकार का व्यवहार संपूर्ण भारत वर्ष में देखने को मिला।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के

कारण सरकार ने संपूर्ण देश में कठोर लॉक डाउन लगाने का कदम उठाया। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है जहाँ अर्थव्यवस्था के हालात भी अधिक मजबूत नहीं है लेकिन फिर भी अपने नागरिकों का जीवन बचाने के लिए सरकार ने लॉक डाउन का जो निर्णय लिया वह अत्यंत प्रशंसनीय है। वहीं दूसरी ओर हम देखें कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रारंभ से ही अपने देश में लॉक डाउन के विरोध में रहे क्योंकि अमरीकन जनता ने एक नेता को नहीं चुनकर एक व्यवसाई को राष्ट्रपति के रूप में चुना जो प्रत्येक निर्णय को आर्थिक लाभ हानि के रूप में देखता है। इसी कारण अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की संख्या अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक रही। जब बड़े-बड़े अर्थशास्त्री और कुछ नेताओं के साथ-साथ आम लोगों को भी डर लग रहा था कि अर्थव्यवस्था की नाजुक हालत को देखते हुए हो सकता है कि 3 मई 2021 के पश्चात लॉक डाउन ना बढ़े परंतु भारतीय नागरिकों के जीवन को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने तीसरी बार भी लॉक डाउन बढ़ाने की घोषणा की जो कि अपने लोगों की जान बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या जहाँ लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर रहे थे यदि सरकार ने उस वक्त लॉक डाउन में ढिलाई बरती होती तो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या करोड़ों में होती और मरने वालों की संख्या लाखों में होती परंतु सरकार ने लॉक डाउन लगाते समय केवल और केवल मात्र जनमानस के जीवन को ध्यान रखा, ना कि अर्थव्यवस्था की अधिक चिंता की। जब लॉक डाउन में स्थिति अत्यंत विकट प्रतीत होने लगी और लोग हताश होने लगे तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक शाम को अपने नागरिकों से थाली चम्मच बजाने का आव्हान किया और भारतवर्ष के अधिकांश घरों में उस नियत समय पर ताली बजाने की घटना हुई। भारत मे ऐसा करने के बाद अनेक देशों में भी इसी प्रकार के प्रयोग कर लोगों को हताशा से बाहर निकालने के लिए प्रयास किये गए। भारत में कुछ लोग यहाँ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए और उन्होंने इसे हास्य के रूप में लिया। ध्यान देने वाली बात है कि चाइना में 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण का पहला केस सामने आया था जबकि भारत में इसका प्रथम केस 30 जनवरी 2020 को आया था जो कि चीन के वुहान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत मेडिकल की तृतीय वर्ष की छात्रा थी जो कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी। भारत में कोविड-19 की अब तक तीन लहर सामने आ चुकी हैं, तथा चतुर्थ लहर आने की चर्चा भी कुछ लोग कर रहे हैं परंतु इस दौरान उपचार का तरीका लगभग एक जैसा रहा।

कोविड-19 से निपटने के लिए कई प्रकार के उपचार का प्रयोग किया गया लेकिन अभी तक भी इसके उपचार का कोई व्यापक स्वीकार्य तरीका उपलब्ध नहीं हुआ है। देश में इसके उपचार के लिए विभिन्न तरीके जैसे प्लाज्मा थेरेपी, रेमेडिसिवर इंजेक्शन व डीआरडीओ के कोविड रोधी दवाई 2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) दवा का प्रयोग किया गया लेकिन फिर भी कोविड-19 ग्रस्त रोगियों के इलाज के लिए कोई पुख्ता दवा आज तक प्राप्त नहीं हुई हैं। कोविड-19 और इसके वर्तमान प्रकार ओमिक्रोन से निपटने के लिए टीकाकरण ही सबसे कारगर साबित हुआ है। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और यहाँ तक की प्रत्येक शहर कस्बे में कचरा संग्रहण करने के लिए घर घर आने वाले वाहन के माध्यम से भी लोगों के कानों तक लगातार यह आवाज पहुँचाई गई कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है। गांव, शहर के लोग भी मोबाइल पर फ्री कॉलर ट्यून के रूप में कोरोना वायरस की चेतावनी को सुन सुनकर पर्याप्त रूप से सचेत और जागरूक हो गए थे। कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्र के लिए उत्पादक बन कर अपने-अपने क्षेत्र में प्रोडक्टिव कार्य किए जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी शीघ्र ही अपनी कोरोना पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगी तथा भविष्य में अर्थव्यवस्था अपने शिखर पर पहुँचेगी ऐसा मेरा विश्वास है। इसके अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण यह है कि किस प्रकार केंद्र सरकार ने लोगों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया प्रयोग में ली। सर्वप्रथम कोरोना से पीड़ित लोगों के मध्य कार्य करने वाले कोरोना योद्धा जिसमें डॉक्टर,

कंपाउंडर, नर्स, सफाईकर्मी, दवा विक्रेता, सुरक्षा व्यवस्था में लगे कार्मिक इत्यादि एवं गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, बीपी एवं अन्य जटिल बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया गया, जिससे कोरोना योद्धाओं द्वारा कोविड-19 के रोगियों के मध्य रहकर उनको इस महामारी से लड़ने में स्वयं की सुरक्षा के साथ उपयोगी योगदान प्रदान किया। इसके पश्चात 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि कई पश्चिमी देशों ने अपने वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में नहीं रख कर केवल युवाओं को ही सर्वप्रथम वैक्सीनेट किया। इसी कारण पश्चिमी देशों में कोरोना संक्रमित होने से मरने वालों में 80 प्रतिशत से अधिक उनके वरिष्ठ नागरिक रहे। इस प्रकार सरकार ने अपनी सनातन संस्कृति जो कि अपने वरिष्ठ व्यक्तियों को सुरक्षा एवं सम्मान देने की है, को संपूर्ण विश्व के सम्मुख प्रदर्शित किया। उक्त प्रकार के व्यक्तियों को वैक्सीनेट करने के उपरांत उन व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया गया, जो कि 45 से 60 वर्ष के मध्य के हैं। इन लोगों को वैक्सीनेशन की प्रथम खुराक देने के पश्चात युवाओं को जो कि 18 से 45 वर्ष के मध्य के हैं, उन लोगों को वैक्सीनेट किए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया। वैक्सीनेशन का कार्य इस प्रकार किया गया कि किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर अधिक भीड़ एकत्र नहीं हो पाई एवं वैक्सीनेशन का संपूर्ण कार्य बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से पूरे भारत में संभव हो पाया।

यह एक प्रकार से भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश जिसमें कि विश्व की द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या है, के लिए पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने वाला कार्य सिद्ध हुआ। कई मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियाँ जिन्हें कि भारत में इस विपदा के समय में अरबों खरबों रुपयों की कमाई की उम्मीद थी, को सरकार के द्वारा भारत में ही विकसित दवाइयों/वैक्सीनेशन के द्वारा उनके द्वारा की जा रही उम्मीद को समाप्त कर दिया। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत में भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई वैक्सीन कोवेक्सीन एवं सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित वैक्सीन कोविशिल्ड भारत में ही तैयार की गई। यह अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में निर्मित इन वैक्सीन की कीमत अन्य देशों में निर्मित वैक्सीन की कीमत से बहुत कम रही। साथ ही सरकार ने इन वैक्सीन को प्रत्येक भारतीय को दो डोज़ नि:शुल्क मुहैय्या करवाई। अब तक लगभग 185 करोड़ से अधिक वैक्सीन व्यक्तियों को नि:शुल्क लगाई जा चुकी हैं। कोरोना काल में भारत अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहा। बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भारत ने कोविड-19 की महामारी में एक बेहतर प्रबंधन कर एक मिसाल कायम की। हालांकि आर्थिक स्थिति पर इस प्रबंधन की कुछ तात्कालिक कीमत चुकानी पड़ी लेकिन अब उसमें भी तेजी से सुधार हो रहा है। भारत में न केवल एक बड़ी हद तक अपने जनमानस को सुरक्षित रखा बल्कि उसने पड़ोसियों का ध्यान रखते हुए निष्क्रिय पड़े हुए दक्षेश जैसे संगठन को भी सक्रिय करने का प्रयास किया। कोरोना महामारी से पहले चाहे मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर और स्वास्थ्य वस्तुओं के उत्पादन एवं उपलब्धता में भारत की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन इस संकट के दौरान ही भारत ने इन वस्तुओं के उत्पादन में महारत हासिल कर दुनिया को अपनी क्षमताओं से अवगत कराया। इस वैश्विक संकट के दौरान भारत स्वास्थ्य संबंधी इन उत्पादों का अग्रणी आपूर्ति करने वाले देश के रूप में उभरा।

आज पूरे विश्व में भारत की वैक्सीन कूटनीति की धूम मची हुई है जबकि चीन के ऐसे ही प्रयास पूर्णत विफल रहे हैं। अफ्रीका के छोटे-छोटे देशों से लेकर अमेरिका, आस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया के विभिन्न देशों तक भारत निर्मित वैक्सीन पहुँची है। कोरोना संक्रमण में वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत भारत के ऐसे प्रभाव का श्रेय निस्संदेह है देश के राजनीतिक नेतृत्व को दिया जाना उचित भी हैं। जिसने दर्शाया कि भारत के पास भले ही संसाधनों की कमी हो लेकिन इच्छाशक्ति की नहीं हैं। कोरोना महामारी के विकट काल में भारत के इन्हीं तत्संबंधी प्रयासों का ही नतीजा है कि विश्व में भारत के प्रति सभी देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। भारत के प्रति उनका सम्मान बढ़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो भारत के गुणगान इस कदर किया है कि उन्होंने भारत को हनुमान जी का प्रतीक बता दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि

जैसे हनुमान जी, लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर पहुँचे थे उसी प्रकार भारत भी ब्राजील के लोगों को बचाने के लिए, अपने यहाँ निर्मित हाइड्रोक्सी फ्लोरो क्वीन की दवाई ब्राजील को एवं अन्य समस्त देशों जिन्हें इसकी आवश्यकता थी को भिजवाया। इस संकट की स्थिति में भारत ने अपनी संस्कृति ''सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया'' को संपूर्ण विश्व के सामने रखा। हम देखते हैं कि इस कोरोना संकट के दौरान भारत के प्रति सदैव शत्रुता का भाव रखने वाले देश पाकिस्तान और चाइना का भी भारत के प्रति रवैया कुछ नरम हुआ है। इसके पीछे अनेक कारणों में से प्रमुख कारण यह रहा कि यदि चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाया तो पूरी दुनिया भारत के पक्ष में एकत्र हो सकती है। इसी कारण पाकिस्तान भी भारत के साथ संघर्ष विराम की पेशकश करता दिखा। भविष्य में स्पष्ट दिख रहा है कि भूराजनीतिक, भूआर्थिक एवं भूसामरिक मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। संपूर्ण वैश्विक पटल पर भी भारत की भूमिका बढ़ी हैं अर्थात् कोरोना के पश्चात वैश्विक स्तर पर भारत की अहम भूमिका हुई है। इस संकट काल में देश का कद उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। कोरोना केवल एक महामारी नहीं होकर समकालीन दौर को निर्धारित करने वाली एक महत्त्वपूर्ण विभाजक रेखा बन गई है। आज प्रत्येक देश में विमर्श के केंद्र, देश की कोरोना वायरस की स्थिति को देखकर हो रहे हैं। कोरोनावायरस से उपजी बीमारी कोविड 19 से विश्व का शायद ही कोई देश बचा हो जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। इस वैश्विक महामारी को आरंभ हुए दो से भी अधिक वर्ष बीत गया है एवं अभी भी इससे पूरी तरह निपटने के लिए कई वर्ष और लग सकते हैं परंतु इस संक्रमण काल में विश्व में अनेक व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। इन परिवर्तनों की प्रकृति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कोरोना के उपरांत की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी।

कोविड-19 महामारी से पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के वर्चस्व में निरंतर वृद्धि हो रही थी। उसके बढ़ते हुए प्रभुत्व पर अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने कुछ अंकुश लगाने के प्रयास भी किए परंतु वह उसमें सफल सिद्ध नहीं हो पाए। यहाँ तक कि चीन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और कानूनों को धता बताते हुए अपनी मनमानी करता रहा। कोरोना वायरस का उद्गम देश कौन है और उसको लेकर संपूर्ण विश्व को अंधेरे में रखने के कारण चीन के विरुद्ध संपूर्ण विश्व में एक विरोधात्मक धारणा बनती गई। इस धारणा को चीन के अपने दबंगई व्यवहार ने भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस प्रकार से धनबल से चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी अपना प्रभाव जमाया तो उससे कुपित होकर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमेरिका का डब्ल्यूएचओ संस्था से नाता तक तोड़ दिया। दुनिया के विभिन्न देश अब कोरोना वायरस को चीन द्वारा फैलाने का दावा कर रहे हैं। परन्तु चीन कोरोना संक्रमण की व्यापक जाँच को लेकर प्रारंभ से ही कन्नी काटता रहा। जब इस दावे का उस पर दबाव पड़ा तो इस हेतु प्रभावी ढँग से माँग कर रहे आस्ट्रेलिया को भी वह धमकी देने से नहीं चूका।इस प्रकार के व्यवहार से जापान, कोरिया, अमेरिका इत्यादि देशों ने चीन की भरपूर आलोचना की। कोरोना पूर्व काल में वैश्विक महाशक्ति बनने की इच्छा रखने वाले देश चीन की उम्मीदों पर कोरोना काल में उसके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने पानी फेरने का काम किया। इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना के पश्चात वाले विश्व में डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं को अपना व्यवहार एवं तरीका बदलना पड़ेगा अन्यथा वे और अप्रासंगिक होती जाएँगी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में इन अंतराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के लिए जोर दिया था। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि वैश्विक संस्थाओं को पूर्व में मिला समर्थन तभी तक स्थिर रह सकेगा जबकि वे अपने कार्य करने की शैली को निष्पक्ष रखें। इसके अतिरिक्त कोरोना संकट ने अनेक अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भी कलाई खोल कर रख दी इन संस्थाओं में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि पूरी दुनिया में कोहराम मचा देने वाली इस महामारी के विरुद्ध इस संस्था ने चीन के व्यवहार के विरुद्ध एक प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। इसी प्रकार डब्ल्यूएचओ भी दिशाहीन दिखाई दिया। परंतु इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना संक्रमण में भारत अपनी

कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्र के लिए उत्पादक बन कर अपने-अपने क्षेत्र में प्रोडक्टिव कार्य किए जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी शीघ्र ही अपनी कोरोना पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगी तथा भविष्य में अर्थव्यवस्था अपने शिखर पर पहुँचेगी ऐसा मेरा विश्वास है। इसके अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण यह है कि किस प्रकार केंद्र सरकार ने लोगों को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया प्रयोग में ली। सर्वप्रथम कोरोना से पीड़ित लोगों के मध्य कार्य करने वाले कोरोना योद्धा जिसमें डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सफाईकर्मी, दवा विक्रेता, सुरक्षा व्यवस्था में लगे कार्मिक इत्यादि एवं गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह, बीपी एवं अन्य जटिल बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया गया, जिससे कोरोना योद्धाओं द्वारा कोविड-19 के रोगियों के मध्य रहकर उनको इस महामारी से लड़ने में स्वयं की सुरक्षा के साथ उपयोगी योगदान प्रदान किया।

एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहा। कोरोनावायरस महामारी पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप बनकर आई परंतु भारत ने इस वायरस रूपी आपदा को अवसर में बदला है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट काल में समस्त भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।

कोरोनावायरस के कारण जहाँ लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गई वहीं दूसरी तरफ इस वायरस ने लोगों में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता भी जगाई है। देशवासियों ने इंटरनेट की मदद से नई-नई वस्तुओं को बनाकर आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन कर दिखाया। वर्तमान में मोदी जी द्वारा दिया गया मंत्र 'वोकल फॉर लोकल' भारत के प्रत्येक घर में गूंज रहा है। जिसके कारण अधिकांश भारतीय घरों में लोग भारत में ही बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। इन विदेशी वस्तुओं में सबसे अधिक बहिष्कार चीन निर्मित वस्तुओं का किया गया जिससे कि चीन को इन दो वर्षों में आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगा। यह सब देशवासियों की एकता के कारण ही संभव हो पाया है। इस महामारी से पूर्व अनेक क्षेत्रों- जैसे खिलौने उद्योग में चाइना का प्रभुत्व था, लेकिन मोदीजी की अपील के बाद बाजार में प्रत्येक ग्राहक 'मेड इन इंडिया' खिलौने की माँग कर रहे हैं। जिससे की दुकानदारों को भी चाइना से इन खिलौनों को नहीं मँगवाने का दबाव हुआ तो वह भी यहाँ के खिलौने बनाने वाले लघु उद्योगपति को भारतीय खिलौने के आर्डर देने लगे हैं जिससे कि पिछले एक-दो वर्षों में ही भारतीय खिलौनों की माँग भारत के साथ अन्य देशों में भी अत्यधिक बढ़ गई है। आज अधिकतर घरों में स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस के प्रारंभ में भारत में मास्क और सैनिटाइजर तक का भी निर्माण अत्यंत सीमित मात्रा में किया जा रहा था।

आज स्थिति यह है कि भारत के उद्योगपति मास्क और सेनीटाइजर भारत के लोगों को तो बहुत उचित कीमत पर उपलब्ध करा ही रहे हैं साथ ही साथ इनका निर्यात भी अनेक देशों को किया जा रहा है। यहाँ तक कि आज भारत वेंटिलेटर का भी निर्यात बाहर के देशों को कर रहा है जबकि कोरोना के प्रारंभ में इन वेन्टीलेटर्स को विदेशों से आयात किया गया था। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह सभी भारत में ही बन रहे हैं और प्रचुर मात्रा में निर्यात भी किए जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में पोलियो की खुराक बीमारी उत्पन्न होने के बाद लगभग 20-25 वर्ष बाद उपलब्ध हो पाई थी। सरकार द्वारा यहाँ के वैज्ञानिकों को भारतीय वैक्सीन शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं उनकी प्रयोगशाला में जाकर उन्हें मोटिवेट करना बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री जी के इस मोटिवेशनल कदम एवं ईश्वरीय शक्ति से यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो उत्कृष्ट वेक्सीन तैयार कर दी। इससे स्वंय सिद्ध है कि भारत मे संसाधनों की कमी तो हो सकती है लेकिन भारतीयों में इच्छाशक्ति की कमी कदापि नहीं है। कोरोना संकटकाल में एक बात जो हमें अपने समाज में देखने को मिली वह यह है कि किस प्रकार अपने पूर्वज साल भर का गेहूँ, चावल, तेल, शक्कर, दाल आदि इकट्ठा करके रख लेते थे तथा अचार वगैरह भी बना कर रख लेते थे जिससे कि यदि कोई विपत्ति भी आए तो भोजन व्यवस्था चलती रहे। इस प्रकार की विशेषता विदेशियों के पास नहीं है। इसी कारण वहाँ के लोग संयुक्त परिवार को नहीं जानते, अकेले रहते हैं और इस कारण से वे मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं हमारी संस्कृति में परिवार के लोग अपने बुजुर्ग व्यक्तियों का ध्यान रखते हैं इस प्रकार की सकारात्मक सोच को नई पीढ़ी ने महसूस किया है अब आवश्यकता यह है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से इस प्रकार की बातों को सीखना चाहिए और पश्चिम की अंधी नकल नहीं करनी चाहिए। ❑

कोरोना का प्रभाव व भारतीय अर्थव्यवस्था

उपेंद्र सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
(राजनीति विज्ञान),
राजकीय महाविद्यालय
चिखली, डूंगरपुर (राज.)

मार्च 2020 से अप्रैल 2022 के मध्य 'गंगा से वोल्गा तक' काफी जल प्रवाहित हो चुका है। इस बीच दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस से कम या अधिक संक्रमित न हुआ हो। इसीलिए इसे वैश्विक महामारी का नाम दिया जा रहा है। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ यह संकट पूरी तरह अनपेक्षित है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया के 190 से अधिक देशों और उनके प्रभाव के अंतर्गत आने वाले लगभग दो दर्जन क्षेत्रों व द्वीपों पर कोरोना वायरस का प्रकोप रहा और अब भी चौथी लहर की आशंका में शेष विश्व के साथ भारत भी अपनी सुरक्षात्मक तैयारियाँ कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर दिनांक 26/4/2022 तक कुल 50, 80, 41, 253 व्यक्ति संक्रमण का शिकार हो चुके हैं जिसमें 62,24,220 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत मृतकों की संख्या के आधार पर तीसरे नम्बर पर है। लेकिन टीकाकरण की दृष्टि से यह पहले स्थान पर है।

इसकी भयावहता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की स्थिति सबसे खराब है। इसे इस तालिका से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है –

देश	–	**मौत**
अमेरिका	–	9,83,989
ब्राज़ील	–	6,62,646
ब्रिटेन	–	1,74,693
फ्रांस	–	1,42,025
भारत	–	5,23,622
रूस	–	3,75,237
चीन	–	14,951

यह तथ्य मृतकों की संख्या को अभिव्यक्त करता है। इसमें चीन में मृतकों की संख्या सबसे कम है लेकिन इन आँकड़ों पर पूरी तरह यकीन करना सम्भव नहीं है। लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से यह अचानक आया और असाधारण तरीके से पूरी दुनिया में फैल गया उससे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यह कहना संभवत: अधिक उचित होगा कि इस महामारी ने धरती के किसी भी गोलार्द्ध में स्थित जन समुदाय के जीवन के समस्त क्षेत्रों जैसे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं को झकझोर दिया है। लेकिन यहाँ एक अलग क्षेत्र का विश्लेषण करने की कोशिश की जाएगी जिसे मार्क्सवादी मान्यताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है अर्थात् आर्थिक क्षेत्र जिसे वर्तमान उदारवादी-पूंजीवादी व्यवस्था के दौर में सबसे प्रभावशाली कारक स्वीकार किया जाता है क्योंकि मानवीय श्रम इस अर्थव्यवस्था का मूल है।

सामान्य रूप से किसी भी देश की मुद्रा आपूर्ति, व्यावसायिक गतिविधियों तथा उद्योग धंधों के संचालन को सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन,

वितरण, विनिमय और उपभोग चार आधारभूत तत्त्व हैं जो मार्क्सवादी देशों में सरकार और उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में बाज़ार में माँग व आपूर्ति के नियमानुसार निर्धारित व नियंत्रित होती हैं। यदि कोरोना संकट के पहले व वर्तमान में आकार के दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो ऊपर की पाँच अर्थव्यवस्थाओं के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किन्तु विकास दर के हिसाब से अर्थव्यवस्थाओं का आकार ज़रूर बदलता रहेगा। एक अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2025 तक ब्रिटेन व जर्मनी से बड़ा हो सकता है। 2019 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का क्रम इस प्रकार था –

1. अमेरिका 21.0 ट्रिलियन (डॉलर)
2. चीन 9.2 ट्रिलियन
3. जापान 5.2 ट्रिलियन
4. जर्मनी 4.2 ट्रिलियन
5. ब्रिटेन 3.2 ट्रिलियन
6. भारत 2.9 ट्रिलियन

वैसे तो कोरोना का पहला मामला चीन में 2019 के अंतिम महीनों में आ चुका था। लेकिन चीन उसे दुनिया से छिपाता रहा। स्थिति अनियंत्रित होने पर 23 जनवरी 2020 को वुहान में पूर्ण लॉकडाउन कर आवागमन को रोक दिया किन्तु उससे पहले ही कोरोना वायरस चीन से निकल कर अमेरिका और यूरोप को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। देखते ही देखते एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया , लैटिन अमेरिका के देशों और यहां तक कि ग्रीनलैंड जैसे द्वीपों पर भी कोरोना ने अपने पाँव फैला लिए थे। जहां तक भारत का सवाल है, यहाँ कोरोना का पहला मरीज़ फरवरी में आया और 21 मार्च 2020 से लॉकडाउन घोषित हो गया जो कई चरणों में आगे बढ़ा और चरणबद्ध तरीके से हटा। दूसरी लहर और ज्यादा घातक थी लेकिन तीसरी से बहुत कम नुकसान हुआ क्योंकि भारत में उससे पहले ही 100 करोड़ टीका लगवाया जा चुका था।

इस ग्लोबल महामारी का सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। यह पूरी तरह स्वाभाविक है क्योकि प्रत्येक बड़े संकट के बाद अर्थव्यवस्था में ह्रास आता ही है। पिछली शताब्दी में और विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के विनाश के बाद तीस के दशक में दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भयानक आर्थिक मंदी का दौर आया था। इसमें भी फ्रांस व ब्रिटेन सहित अनेक यूरोपीय देश बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इटली, जापान व जर्मनी की हालत तो और भी बदतर थी क्योंकि ये पराजित राष्ट्र थे। डॉलर की तुलना में इनकी मुद्राओं का मूल्य हज़ारों गुना नीचे गिर गया था। पहली लहर में तो अनेक लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए सक्षम नहीं थे।

कोरोना की दूसरी लहर (मार्च 2021) में मानवीय क्षति सर्वाधिक रही लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से इसका नकारात्मक प्रभाव पहली लहर (मार्च 2020) से कम रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के खत्म होते होते विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 3 प्रतिशत का प्रारम्भिक संकुचन हुआ जो कि महान आर्थिक मंदी के बाद सबसे तीव्र ह्रास है। लॉकडाउन में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी सरकारों ने लगभग एक जैसी नीति का ही पालन करते हुए कुछ अपवादों के साथ कर्फ़्यू लगा दिया जिससे उद्योग, फैक्टरी, बाज़ार, उत्पादन, विक्रय सब बन्द हो गए क्योंकि क्रेता व विक्रेता दोनों ही अपने अपने घरों में बंद थे। आपूर्ति शृंखला भी बुरी तरह प्रभावित हुई क्योंकि ट्रांसपोर्ट को भी सीमित कर दिया गया था। यात्री ट्रेन व हवाई यात्रा तो पूर्णत: बंद थी। इसने पर्यटन क्षेत्र को शून्य कर दिया। केंद्रीय यूरोप के देश इटली की स्थिति की बदहाली का एक कारण यह भी है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का विशेष स्थान है। पर्यटन के प्रतिबंधित होते ही

उनपर निर्भर तमाम व्यवसाय भी लगभग बंद हो गए। भारत में भी पर्यटन उद्योग सबसे बुरी स्थिति का सामना कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन लगभग बन्द है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय ट्रेवेल एजेंसी, होटल , रेस्त्रां और गाइड की आमदनी का स्रोत भी कम हो गया। स्थानीय पर्यटन के खुल जाने से होटल व रेस्त्रां का व्यापार सुधरा है लेकिन विदेशी पर्यटकों के लिए गाइड का काम करने वाला एक बड़ा वर्ग चिंतनीय आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है।

2020 में यह अधिकांश देशों में हुआ। इसलिए भारत में भी आर्थिक मंदी का दौर शुरू होना ही था। मंदी का अर्थ जहाँ एक तरफ अर्थव्यवस्था के आकार का सिकुड़ना है वहीं दूसरी तरफ विकास दर भी कम होती है। इसका प्रभाव निर्माण क्षेत्र में उत्पादन और बाजार में माँग में कमी किन्तु बेरोजगारी में वृद्धि के रूप में सामने आया है। निजी क्षेत्र में हानि को कम करने के लिए नई भर्ती पर रोक और पुराने कर्मचारियों की छटनी की गई जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश यानि संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी में सरकारी सहायता (लाभ) के लिए सिर्फ अप्रेल 2020 में ही लगभग 20.5 मिलियन लोगों ने आवेदन किया था।

संगठित क्षेत्र हो या असंगठित किन्तु एक बात निश्चित है कि सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके साथ एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्तमान आर्थिक मंदी से विकसित अर्थव्यवस्थाएँ अधिक प्रभावित होंगी। इसका कारण यह है कि और विकसित या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था आएँ उल्टा कृषि पर आधारित होती हैं जिस जिसके कारण पर औद्योगिक राष्ट्रों की तुलना में कम प्रभावित होंगे इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देश आर्थिक दृष्टि से अधिक प्रभावित होंगे और इनकी अर्थव्यवस्था है विकासशील देशों की तुलना में अधिक संकुचित होंगी। 2020 के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अन्य अध्ययन के अनुसार यदि चीन को विकसित देशों में से निकाल दिया जाए तो सामान्य रूप से विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएँ 2.2 प्रतिशत की दर से संकुचित होंगी जबकि अल्पविकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में 1 प्रतिशत की दर से संकुचन होगा।

इस बिंदु पर एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना जरूरी है कि सामान्य रूप से सभी देशों के जीडीपी में गिरावट आई है। यूरोप के देश विशेषकर फ्रांस, इटली और स्पेन की जीडीपी औसत रूप से 19.5 प्रतिशत की दर से गिरी है जबकि चीन की जीडीपी 2020 के पहले क्वार्टर में 36.6 प्रतिशत की दर से गिरी थी किंतु अभी हाल के अध्ययन से पता चलता है कि लॉकडॉउन खत्म होने के बाद जब वहाँ उद्योग-धंधे और कल-कारखाने पुनः प्रारंभ हुए तो चीन की अर्थव्यवस्था में अन्य देशों की तुलना में ज्यादा तीव्र गति से सुधार देखने को मिल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था जुलाई 2020 में 3.2 प्रतिशत की दर से विकसित हो रही है जो कि अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत अच्छी है। विदित हो कि दूसरी तिमाहीं में भी चीन की अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतिशत की दर से घटी थी। इसी क्रम में भारतीय जीडीपी की विकास दर-23 प्रतिशत तक हो गई थी। किन्तु अमेरिका व ब्रिटेन की हालत तो भारत से भी दयनीय हो गई थी।

भारत की आबादी चीन के बाद दुनिया के किसी भी देश से बहुत अधिक है। फिर भी यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत, जिसकी 60 प्रतिशत आबादी अब भी कृषि पर निर्भर करती है वहाँ, की अर्थव्यवस्था उस रूप में कभी भी प्रभावित नहीं होगी जिस रूप में विकसित देशों की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएँ अधिक प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' की योजनाओं का लाभ भी देश को मिलने लगा है। हम इन आर्थिक संकेतों से विश्वास कर सकते हैं कि 2022 के समाप्त होते-होते भारत न केवल कोरोना से मुक्त हो जाएगा बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था भी कोविड के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त होकर पहले की अपेक्षा तेज गति से आगे बढ़ेगी और भारत एक सशक्त आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व राजनीति को एक दिशा देगा।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बात और भी उल्लेखनीय है कि पहले सामान्यतः आर्थिक मंदी का सामना विश्व युद्धों के बाद या बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि या कठोरता अथवा तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अत्यधिक बढ़ाने के बाद किया गया था। सन् 2020 में माँग कम होने से पेट्रोल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें न्यूनतम स्तर तक चली गई थी किन्तु रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इसमें फिर तेजी आ रही है जिसका प्रभाव भारत में मंहगाई पर भी पड़ेगा। यह अलग बात है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए हो रहे खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकारों ने दाम नहीं घटाए क्योंकि पैसे से अधिक महत्त्वपूर्ण लोगों का जीवन बचाना है। सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदारहण यह है कि अब तक 26 अप्रैल 2022 तक वैक्सीन की 1,88,16,99,433 डोज़ भारतीयों को लग चुकी है। जिससे न केवल लोगों में आत्मविश्वास आया है बल्कि अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ रही

है। शेयर मार्केट भी लंबे समय तक नीचे गिरता लेकिन अब उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों में विकास की संभावना निवेशकर्ताओं को दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए आज 27/4/22 को सेंसेक्स 58568 पर बंद हुआ। कोरोना काल में 2020-21 में 27000 तक गिरने के बाद 2022 में उच्चतम 62000 तक पहुँचना एक शुभ संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब तेजी से पटरी पर आ रही है। जब कभी शेयर मार्केट नीचे जाता है तो सोने और चांदी के मूल्य ऊपर उठते हैं । 2020 में सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल आया है और सोने की कीमत 58000 रु प्रति दस ग्राम तक पँहुच गई थी। जिसके कारण भारत जैसे देश में, जहाँ शादी-विवाह में भारी मात्रा में सोने चांदी का उपयोग किया जाता है वहां, परिवारों की अर्थव्यवस्था भी डगमगाने लगती है। अब सोना 50000 रु के आस पास है। भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक है वहाँ बड़े शहरों से मजदूरों के पलायन से जहाँ एक तरफ शहरों में कल-कारखानों के लिए मजदूरों की संख्या घटी वहीं दूसरी तरफ गाँव में कृषि पर अनावश्यक बोझ भी बढ़ा। किन्तु अब मज़दूर वर्ग शहरों में लौट चुका है जिसके कारण व्यापार व और अर्थव्यवस्था की तरलता बढ़ी है।

सच बात यह है कि इस अनपेक्षित संकट के लिए कोई तैयार नहीं था। अलग-अलग देशों ने कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाने का प्रयास किया। भारत में बड़े शहरों से मजदूरों के पलायन ने समस्या को और भी विकट कर दिया जिससे निपटने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके पूर्व के बजट (2020-21) में मध्यम, छोटे आकार तथा माइक्रो स्तर के उद्योगों के लिए कई योजनाएँ और राहत पैकेज दिए। उन्होंने किसानों, मजदूरों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों तथा ठेला और रेवड़ी लगाने वाले व्यक्तियों के लिए भी विशेष राहत पैकेज प्रदान किए। अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया जो देश के जीडीपी का कुल 10 प्रतिशत थी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह धनराशि इटली, फ्रांस या स्पेन (5.6 प्रतिशत) द्वारा घोषित पैकेज से अधिक थी। इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21) भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी से उभरने की उम्मीद साफ़ साफ़ दिखलाता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अनन्त नागेश्वरन की अध्यक्षता में किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 9.2 प्रतिशत रहेगी। इसी प्रकार इस सर्वेक्षण के अनुसार 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। यह अलग बात है कि इस अवधि में भारत सरकार को आधारभूत अधिसंरचनाओं के विकास के लिए 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करना पड़ेगा। इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारतीय जीडीपी 8 से 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

विदित है कि 2021-22 में औसत विकास दर 5.6 प्रतिशत थी। इस सर्वेक्षण को वैश्विक संस्थाओं के अध्ययन से भी बल मिलता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार भी भारत की जीडीपी की विकास दर 8.7 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 -21 और 2022-23 में भारतीय जीडीपी 9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से धीरे- धीरे मुक्त हो रही है इसका एक प्रमाण यह भी है कि कृषि (3.9 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र (8.2 प्रतिशत) और उद्योग क्षेत्र (11.8 प्रतिशत) में भी तेजी से विकास हो रहा है। बजट पूर्व भारत सरकार में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। राजस्व प्राप्ति में भी पिछले साल (2020) के 9.6 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2021 में 7 गुना अधिक वृद्धि देखी गई है।

यहाँ यह बात भी नहीं उल्लेखनीय है कि भारत की आबादी चीन के बाद दुनिया के किसी भी देश से बहुत अधिक है। फिर भी यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत, जिसकी 60 प्रतिशत आबादी अब भी कृषि पर निर्भर करती है वहाँ, की अर्थव्यवस्था उस रूप में कभी भी प्रभावित नहीं होगी जिस रूप में विकसित देशों की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएँ अधिक प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' की योजनाओं का लाभ भी देश को मिलने लगा है। हम इन आर्थिक संकेतों से विश्वास कर सकते हैं कि 2022 के समाप्त होते-होते भारत न केवल कोरोना से मुक्त हो जाएगा बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था भी कोविड के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त होकर पहले की अपेक्षा तेज गति से आगे बढ़ेगी और भारत एक सशक्त आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व राजनीति को एक दिशा देगा। पूरी दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध करवा कर भारत ने जो अंतरराष्ट्रीय साख प्राप्त की है उसका प्रभाव अभी चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में साफ-साफ देखने को मिल रही है जब पूरी दुनिया भारत के निर्णायक हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा है। ❑

कोरोना वायरस व आर्थिक प्रभाव

डॉ. रेनू यादव

सहायक आचार्य इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, हरियाणा केन्द्रीय वि.वि. महेन्द्रगढ (हरियाणा)

दिसम्बर 2019 में चीन के बहुान शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी (वायरस) ने कहर बरपाना शुरू किया। वहाँ से यह बीमारी देखते ही देखते विश्व के लगभग सभी देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इसकी भयावहता को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे महामारी घोषित कर दिया। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ लॉकडॉउन घोषित किया और लगभग सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में बंद हो गई।

भारत में कोरोना वायरस का आर्थिक प्रभाव

कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालें तो यह प्रतीत होता है कि इस वायरस की वजह से समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी के साथ-साथ अनुत्पादक होती गई जिससे इस वायरस से विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित हुई। सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई जो आगे जाकर मन्दी का कारण बन सकती है। कोरोना वायरस के प्रभाव से अभी हाल ही में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी वहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ इसी राह पर अब नेपाल भी चल पड़ा है।

निवेशकों के बाजार से बाहर निकलने के कारण शेयर बाजार सूचकांक भी प्रभावित हुआ जिसकी वजह से लगातार गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी बाजार में जहाँ 12 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में भी गिरावट का क्रम लगातार देखने को मिला।

भारत में कोरोना वायरस महामारी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव काफी हद तक विघटनकारी रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर घटकर 3 प्रतिशत रह गई थी। महामारी की वजह से बाजार में अस्थिरता और लॉकडाउन के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा जिससे भारत में बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि हुई, आपूर्ति शृंखला में बाधा उत्पन्न हुई, सरकारी आय में कमी आई, पर्यटन उद्योग का पतन हुआ। ईंधन की खपत में गिरावट होने तथा एलपीजी की बिक्री में वृद्धि होने जैसी समस्याएँ मुँह बाए खड़ी हो गई।

कोरोना वायरस से चीनी अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने से भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। आयात एवं निर्यात दोनों प्रभावित हुए क्योंकि भारत अपने कुल आयातित माल का 18 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक घटक का 67 प्रतिशत एवं उपभोक्ता व टिकाऊ वस्तुओं का 45 प्रतिशत चीन से आयात करता है। यह महामारी न केवल आपूर्ति शृंखला को ही प्रभावित कर रही है बल्कि भारत व विश्व के फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से उच्च मुद्रास्फिति की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे आगामी

समय में माँग में वृद्धि से उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। वायरस जनित संकट वित्तीय संकट से बिल्कुल अलग है। दूसरे संकटों का समाधान आर्थिक विधियों व तकनीकी से हो सकता है, परन्तु वायरस जनित संकट का समाधान इन वित्तीय उपायों से संभव नहीं है। हालाकि सरकार द्वारा लगातार विकास की गति का अवलोकन कर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। नई-नई योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए आर.बी.आई. के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने आर्थिक विकास के लिए बजट 2022 से पहले सरकार को सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ-साथ कुछ काले धब्बे भी हैं। महामारी से उबर रही अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार के लिए इन चुनौतियों को दूर करना होगा। सरकार को सावधानी से खर्च करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे राजकोषीय घाटे को बहुत ऊँचाई पर पहुँचने से रोका जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को जिन चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरी है वो निम्न हैं -

1. एम.एस.एम.ई. और बेरोजगारी - बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है।

2. मुद्रा की तरलता बनाए रखना - बाजार में मुद्रा का बने रहना मुश्किल हो रहा है। मुद्रा की तरलता वस्तु की माँग व पूर्ति पर आधारित है जब तक बाजार में माँग व पूर्ति बाधित रहेगी तो मुद्रा की तरलता भी बाधित ही रहेगी।

3. शेयर मार्केट में गिरावट।

4. एफडीआई में कमी - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कमी यानि विदेशी मुद्रा भण्डार का कम होना जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विकास को प्रभावित करता है। जिसकी वजह से रोजगार में कमी आयेगी, आधारभूत संरचना में गिरावट आएगी। चीन, बांग्लादेश व पाकिस्तान को भारत में निवेश करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसी सन्दर्भ में आई.टी.आई. मुम्बई की एक रिपोर्ट में लिखा है कि इससे 12 लाख करोड़ का नुकसान होगा तथा मनरेगा में एक लाख 16 हजार करोड़ का नुकसान होगा। इसको रोकने के लिए बड़ी कंपनियाँ फण्ड छोटे व मझोले उद्योगों के लिए जारी करें।

सरकार के उपाय

सरकार द्वारा महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इसमें समग्र आर्थिक पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपये दिये गये। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है।

कोरोना के प्रभाव से निकालने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि आई.एम.एफ (IMF) ने जनवरी-दिसम्बर 2022 के बीच भारत की आर्थिक विकास दर 9.6 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान जताया है। 2020 में भारत को दुनिया की सबसे तेजगति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है। 2022 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से निकलकर फिर उड़ान भरने की ओर अग्रसर है।

सरकार द्वारा लोगों के खाते में 36 हजार करोड़ रुपये स्थानान्तरित किये।

औद्योगिक क्षेत्र की वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा Insolvency and Bankruptey Code 2016 में संशोधन करते हुए डिफाल्टर की सीमा एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई।

बाजार में मुद्रा की तरलता बनी रहे उसके लिए दो स्तरों पर प्रयास किए गए - 1. सरकार द्वारा, 2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।

सरकार द्वारा राजकोषीय नीति के तहत घोषणाएँ की तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के तहत मूल्य को स्थिर रखने का प्रयास किया है तथा रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट में कमी की गई है। शेयर मार्केट में उछाल के लिए 03 माह तक किसी को ऋण व ई.एम.आई. नहीं देना तथा शेयर मार्केट में लाभांश का भुगतान नहीं करना जैसे प्रयास लगतार किये गये।

भारतीय वर्तमान राजनीति को अर्थव्यवस्था व स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए। राशन कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाना। स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार कार्यक्रमों पर ध्यान देना।

इस तरह से कोरोना के प्रभाव से निकालने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि आई.एम.एफ (IMF) ने जनवरी-दिसम्बर 2022 के बीच भारत की आर्थिक विकास दर 9.6 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान जताया है। 2020 में भारत को दुनिया की सबसे तेजगति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है। 2022 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से निकलकर फिर उड़ान भरने की ओर अग्रसर है। ❑

कोरोना का प्रभाव और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति

डॉ. अनूप कुमार आत्रेय

सहायक आचार्य,
अर्थशास्त्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राज.)

कोविड-19 महामारी के कारण न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था अपितु सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस महामारी ने आर्थिक संकुचन उत्पन्न कर रोजगार, उत्पादन व आय के वैश्विक प्रवाह को बाधित कर दिया है। महामारी की नयी लहरें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नयी चुनौतियाँ लाती रही हैं।

महामारी की विभिन्न लहरों के बीच अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता

कोविड के कारण उत्पन्न आर्थिक संकुचन के चक्र को तोड़ने के लिए तथा आर्थिक क्रियाओं के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से किए गए प्रयासों का ही यह परिणाम है कि वैश्विक आर्थिक पर्यावरण की अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जहाँ लोगों में अपने जीवन और आजीविका को लेकर निश्चितता है।

विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तीव्र गति ने अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के भय से न केवल भयमुक्त किया अपितु आर्थिक क्रियाओं को फिर से पटरी पर लाने का कार्य किया। यह टीककरण अभियान कोविड-19 की लहरों के कारण उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितता व संकटों के समक्ष एक प्रतिरोधक का कार्य कर रहा है।

आर्थिक क्रियाओं का विस्तार भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति के सूचक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को देखा जाए तो देश में आर्थिक क्रियाओं का विस्तार देश में उज्ज्वल आर्थिक भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के आपूर्ति पक्ष एवं माँग पक्ष दोनों ही आधारों के भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के GDP में 7.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार GDP की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। विश्व बैंक ने भी वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक GDP में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक ने भी भारत के वास्तविक GDP में इस वर्ष के लिए 7.5 प्रतिशत वृद्धि की संभावना व्यक्त की है।

25 जनवरी 2022 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों में वर्ष 2022-23 में भारत के वास्तविक GDP में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान दिया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए यह अनुमान 7.1 प्रतिशत दिया गया है।

सशक्त आपूर्ति पक्ष सरकार के आपूर्ति पक्ष के सुधारों का ही यह परिणाम है कि

महामारी से उत्पन्न व्यवधानों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है।

GDP की क्षेत्रवार संरचना पर यदि दृष्टि डाली जाए तो वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3.9 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 11.8 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

महामारी का प्रभाव कृषि क्षेत्र पर सबसे कम देखा गया। महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण औद्योगिक व सेवा क्षेत्र का संकुचन हुआ, उसमें भी अपेक्षाकृत सेवा क्षेत्र पर अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। परन्तु वर्ष 2021-22 में दोनों ही क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। वर्ष 2020-21 में औद्योगिक क्षेत्र में 7 प्रतिशत की गिरावट तथा सेवा क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 में औद्योगिक व सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 11.8 प्रतिशत तथा 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

माँग पक्ष में सुधार सकल घरेलू उत्पाद के माँग पक्ष के सभी घटकों में भी व्यापक सुधार देखे गये हैं। महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में कुल उपभोग व्यय में 7.3 प्रतिशत की कमी हुई थी परन्तु आर्थिक क्रियाओं के प्रवाह में वृद्धि से वर्ष 2021-22 में यह 7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इसी प्रकार कुल स्थायी पूंजी निर्माण अथवा निवेश में वर्ष 2020-21 में 10.8 प्रतिशत की कमी के पश्चात् वर्ष 2021-22 में 15 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है जो कि अर्थव्यवस्था में रोजगार, उत्पादन व आय के स्तरों पर आगामी वर्षों में अनुकूल प्रभाव डालेगी। महामारी के कारण वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यातों में 4.7 प्रतिशत की कमी हुई थी। जिसमें वर्ष 2021-22 में 16.5 की वृद्धि प्रत्याशित है। इसी प्रकार आयातों में वर्ष 2020-21 में 13.6 प्रतिशत की कमी हुई थी जो कि वर्ष 2021-22 में 29.4 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।

महामारी को लेकर विश्व में बनी अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न करने वाले वैश्विक संकट, विभिन्न देशों के मध्य आपसी सामंजस्य का स्तर, तेल की कीमतें आदि अनेक ऐसी भविष्य की चुनौतियाँ है जिस पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर टिकी हुई है। देश में हो रहे संरचनात्मक, संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन, भावी आर्थिक संभवनाओं का निस्तारण कर महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकुचन को समाप्त कर देश के आर्थिक पर्यावरण को सशक्त बनाऐंगे।

संस्थागत एवं नीतिगत प्रक्रियाएँ भारत में महामारी द्वारा लाए गए आर्थिक संकुचन से निपटने के लिए सरकार द्वारा माँग पक्ष के स्थान पर आपूर्ति पक्ष को महत्त्व दिया गया है। निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कर ढाँचे का सरलीकरण, विभिन्न क्षेत्रों का विनियमन आदि उपायों व सुधारों द्वारा आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने का योजनाबद्ध प्रयास किया गया है। उद्योग, बीपीओ, दूरसंचार, विमानन, बैंकिंग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, अंतरिक्ष व भूस्थानिक क्षेत्र, रक्षा आदि प्रत्येक दिशा में आपूर्ति पक्ष को सुदृढ़ किया गया।

यह भारत में चलाए जा रहे व्यापक टीकाकरण अभियान, आपूर्ति पक्ष के सुधारों का ही परिणाम है कि वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर में 7.3 प्रतिशत की भारी गिरावट के पश्चात् आज 2021-22 में वास्तविक रूप में 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है।

महामारी को लेकर विश्व में बनी अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न करने वाले वैश्विक संकट, विभिन्न देशों के मध्य आपसी सामंजस्य का स्तर, तेल की कीमतें आदि अनेक ऐसी भविष्य की चुनौतियाँ हैं जिस पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर टिकी हुई है। देश में हो रहे संरचनात्मक, संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन, भावी आर्थिक संभवनाओं का निस्तारण कर महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकुचन को समाप्त कर देश के आर्थिक पर्यावरण को सशक्त बनाऐंगे। ❑

भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी तीन वर्ष तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था - सदन पटल पर रखे गये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, वर्ष 2022-23 में 'सकल घरेलू उत्पाद' की विकास दर 8-8.5 प्रतिशत रह सकती है। वर्ष 2022-23 से संबंधित यह अनुमान 'विश्व बैंक' और 'एशियाइ विकास बैंक' की क्रमशः 8.7 एवं 7.5 प्रतिशत जीडीपी विकास की संभावना के अनुरूप है।

भारतीय अर्थव्यवस्था : गौरवशाली अतीत से उन्नत भविष्य की ओर

मनोज भारी
सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, सिरोही (राज.)

भारत प्रारम्भ से ही शक्ति तथा सम्पन्नता की धरा के रूप में अस्तित्व में रहा है, इसका आकार एवं इससे जनित विविधता को सांस्कृतिक समरसता तथा सहिष्णुता ने निरंतर सम्पूरकता प्रदान की है। भारत एक समय में सोने की चिडिया कहलाता था। 'आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन' के अनुसार पहली सदी से लेकर दसवीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली सदी में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विश्व के कुल जीडीपी का 32.9 प्रतिशत था, सन् 1000 में यह 28.9 प्रतिशत था और सन् 1700 में 24.4 प्रतिशत था। ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण व दोहन हुआ जिसके फलस्वरूप 1947 में आजादी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुनहरे इतिहास का एक खंडहर मात्र रह गई।

ब्रिटिश राज के अंत तथा विभाजन की त्रासदी के बावजूद उत्तर औपनिवेशिक राज्य के रूप में वर्तमान में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवें स्थान पर है, इसका 2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ जनसंख्या में दूसरा स्थान है जो विश्व की जनसंख्या का 17 प्रतिशत है व भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस गौरव पूर्ण स्थिति में आने से पूर्व भारत को 1991 में भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। 1991 से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति के कारण भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई है और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया है। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण का बोलबाला था। 21 वीं सदी से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता का दौर आरम्भ वस्तुतः आजादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा, सार्वजनिक उद्योगों तथा केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया, पर समाजवादी गढ़ सोवियत संघ के पतन के बाद भारत ने आर्थिक सुधारों की लंबी कवायद शुरु की, जिससे धीरे-धीरे भारत विदेशी पूँजी निवेश का आकर्षण बना और अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना। अप्रत्याशित रूप से वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भारत ने 7.9

प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का एक संकेत समझा गया। 21 वीं सदी से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता का दौर आरम्भ हुआ। 2004-05 से 2011-12 के दौरान भारत की वार्षिक विकास दर औसतन 8.3 प्रतिशत रही किंतु वैश्विक मंदी की मार के चलते 2012-13 और 2013-14 में 4.6 प्रतिशत की औसत पर पहुँच गई। यह 2013-6.39, 2014-7.41, 2015 -8, 2016-8.26, 2017- 6.80 तथा 2018 में 6.53 प्रतिशत रही 2019 में यह 4.04, 2020 में - 7.96 व 2021 में 8.9 प्रतिशत रही।

भारत अब विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप्स इकोसिस्टम

सतत् राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति के परिणामस्वरूप अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2 प्रतिशत के स्तर पर सीमित रखने में सफलता मिली है।

मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष में निम्न आधार, आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि तथा अन्य आयातित वस्तुओं और उच्च माल ढुलाई लागत के कारण से रही। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप्स इकोसिस्टम बन गया है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14 हजार से अधिक हो गई है जो वर्ष 2016-17 में केवल 735 थी। 44 भारतीय स्टार्ट-अप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया, इससे यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स की कुल संख्या 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में हैं। भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जो कोविड-19 के टीके तैयार कर रहे हैं। देश ने भारत में बने दो कोविड-19 टीकों के साथ शरुआत की। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन (COVAXIN), भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित और निर्मित की गई थी। टीकाकरण की प्रगति को न केवल स्वास्थ्य प्रतिक्रिया संकेतक के रूप में देखा जाना चाहिये बल्कि बार-बार महामारी की लहर के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के खिलाफ एक बफर के रूप में भी देखा जाना चाहिये।

महामारी के बावजूद आईपीओ में पिछले दशक से अधिक निवेश

महामारी के बावजूद पूंजी बाजार में तेज वृद्धि अप्रैल-नवम्बर 2021 के दौरान 75 आईपीओ जारी करके 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जुटाई गई, जो पिछले दशक के किसी भी वर्ष की तुलना में काफी अधिक है, भारत की जीडीपी चौतरफा टीकाकरण, आपूर्ति सुधार और नियमन में आसानी से होने वाले लाभ, निर्यात में तेज बढ़ोतरी और पूंजी खर्च करने में तेजी लाने के लिए वित्तीय मौके की उपलब्धता की मदद से वर्ष 2022-23 में 8.0-8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कहा गया है कि आने वाले साल में निजी क्षेत्र में अधिक निवेश होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु मदद के लिए वित्तीय व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। वर्ष 2022-23 में इस वृद्धि का अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि अब महामारी संबंधित और आर्थिक बाधाएँ नहीं आएंगी, मॉनसून सामान्य रहेगा, दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तरलता की निकासी बड़े स्तर पर समझदारी के साथ होगी। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि उपर्युक्त अनुमान की तुलना विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि में क्रमशः 8.7 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के हालिया अनुमान से की जा सकती है। 25 जनवरी 2022 को जारी आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) वृद्धि अनुमान के अनुसार, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी के 9 प्रतिशत की दर से और 2023-24 में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह भारत को इन तीनों वर्ष में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है।

भुगतान संतुलन पिछले दो वर्षों के दौरान अधिशेष में

निर्यात और आयात मोर्चे पर, सर्वेक्षण कहता है कि भारत का माल एवं सेवा निर्यात 2021-22 में काफी हद तक बहुत मजबूत हो रहा है। 2021-22 के आठ महीनों में उत्पाद निर्यात, महामारी से संबद्ध बहुत सी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बावजूद 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा है। कुल सेवा निर्यात में भी तीव्र उछाल आया है और यह उछाल व्यावसायिक और प्रबंधन सलाहकार सेवाओं, ऑडियो-विजुअल और संबद्ध सेवाओं, माल ढुलाई सेवाओं, दूर संचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के माध्यम से आया है। समीक्षा यह दर्शाती है कि वैश्विक महामारी से उत्पन्न सभी अवरोधों के बावजूद भारत का भुगतान संतुलन पिछले दो वर्षों के दौरान अधिशेष में बना रहा। इससे भारतीय रिजर्व बैंक को अपना विदेशी मुद्रा भंडार संचित रखने में मदद मिली। यह भंडार 31 दिसम्बर, 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह आयात के 13.2 महीनों के समतुल्य और देश के बाह्य ऋण से अधिक है।

इस बात की प्रबल आशा व्यक्त की गई है कि व्यापक आर्थिक स्थायित्व संकेतक यह इंगित कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तत्पर है और इसका एक कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी विशिष्ट प्रतिक्रिया रणनीति के तहत अच्छी स्थिति में है। वर्ष 1990 में वैश्विक जीडीपी 38,000 अरब डॉलर था। आज 30 साल बाद यह आँकड़ा 90,000 अरब डॉलर है। अगले तीस साल में यानी 2050 में जीडीपी 1,70,000 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। ❑

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. सुधीर कुमार श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग रानजी
सहाय पीजी कालेज,
रूद्रपुर-देवरिया (उ.प्र.)

सर्व विदित है कि वर्ष 2019 में चीन के बुहान से उत्पन्न कोरोना वायरस ने पूरी मानव सभ्यता को हिला कर रख दिया। यह एक ऐसा वायरस था जिसके बारे में चिकित्सा विज्ञानियों को बहुत जानकारी नहीं थी। ऐसे में यह वायरस चिकित्सा विज्ञान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा। तीव्र संक्रमण और कोई उपचार न होने के कारण पूरे मानव समाज के सामने भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी। दुनिया के ऐसे देश भी जो चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ माने जाते रहे हैं, वह भी इसके संक्रमण को रोकने में असहाय हो गये। फिर शुरू हो गया मौत का ताण्डव। यह मंजर इतना खतरनाक था कि कब्रिस्तान और श्मशान घाट लाशों से पटने लगे। चूँकि इस वायरस का संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति में सम्पर्क के कारण हो रहा था इसलिए शारीरिक सम्पर्क पर रोक लगा देना ही एक मात्र तात्कालिक कारगर उपाय था जिसके लिए लॉक डाउन ही एक मात्र विकल्प शेष था। फलतः जिन देशों में कोरोना का लक्षण मिलना शुरू हुआ वहाँ लॉक डाउन लगना शुरू हो गया। देखते देखते बहुत ही कम समय में विश्व के अधिकांश देशों में लॉक डाउन लग गया। सभी अपने अपने घरों में कैद होने लगे। जो संक्रमित होते वे हास्पिटल में भर्ती होने लगे। उद्योग-धन्धे, यातायात, स्कूल, कालेज, बाजार आदि बन्द हो गये। पूरी मानव सभ्यता ठप हो गयी। जिसका सीधा सीध प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। इस बीमारी से बचाव का एक मात्र तात्कालिक उपाय था दो गज की दूरी, मास्क लगाना और साबुन से हाथों का धुलते रहना या सेनेटाइजर का प्रयोग करना। विश्व के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती के स्वीकार किया तथा तमाम जान की आहुतियों के बाद अन्ततः वैक्सीन का निर्माण कर ही दम लिया और कोरोना के संक्रमण को रोकने में आशातीत सफलता प्राप्त कर ली। परन्तु इस कार्य में लगे दो वर्षों ने मूरे मानव समाज को अस्त-व्यस्त कर दिया।

भारत जैसा देश जिसकी आधी से अधिक आबादी गाँवों में निवास करती है, भी इस बीमारी से अछूता नहीं रहा। बल्कि अशिक्षा, जागरूकता के अभाव के कारण यहाँ यह चनौती बड़ी थी। गाँवों का दर-दर तक विखरा होना एवं यातायात के साधनों का पर्याप्त न होने के कारण यहाँ चुनौती बड़ी थी। अधिकांश ग्रामीण जनता की आय का स्रोत कृषि एवं कृषि सम्बन्धी व्यवसाय ही है। ऐसे में ग्रामीण कृषि व्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव सीधा-सीधा पड़ा। ग्रामीणों का नगरों से सम्पर्क टूट गया। खाद, बीज एवं अन्य कृषि सम्बन्धी संसाधन न उपलब्ध हो पाने से कृषि व्यवस्था लड़खड़ा गयी। फलत-ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी संकट में आ गयी। जिससे ग्रामीण जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यद्यपि एक लम्बे संघर्ष के बाद भारत में भी वैक्सीन का निर्माण हुआ और एक बहुत बड़े अभियान के तहद लोगों को टीका लगाया गया। आज भारत

में भी लगभग कोरोना पर विजय प्राप्त किया जा चुका है। किन्तु अभी भी अर्थव्यवस्था एवं जन-जीवन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। इसके लिए गहन चिन्तन मनन एवं कारगर उपाय की आवश्यकता है। विशेषकर गाँवों में प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण जन-जीवन पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है यह जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण जनता का कोरोना के प्रति क्या नजरिया है और किस प्रकार से वे अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उन उपायों को भी ढूँढ़ना है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती प्रदान करते हुए ग्रामीण जन-जीवन को ठीक किया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में एक अभिनव प्रयास प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रूद्रपुर ब्लाक के ग्रामीणों के अध्ययन पर आधारित है। जहाँ से 50 उत्तरदाताओं का चयन सोद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनकर्ता का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जन-जीवन पर कोरोना प्रभाव का अध्ययन करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ उन उपायों को भी ढूँढ़ना है जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती प्रदान की जा सके। इस निमित्त प्रस्तुत अध्ययन में अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक एवं निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक सूचनाओं के संकलन के लिए एक स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। द्वैतीयक सूचनाओं के लिए पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, शोधपत्रों आदि का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में देवरिया जनपद के रूद्रपुर ब्लाक में निवास करने वाले ग्रामीणों को अध्ययन समग्र के रूप में चुना गया है। सूचना प्राप्ति के लिए परिवार के मुखिया को जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों सम्मिलित हैं को सूचनादाता के रूप में चयनित किया गया है। अध्ययन समग्र के सूचनादाताओं से प्राप्त सूचनाएं इस प्रकार हैं। सर्वेक्षित सम्भाग के शत प्रतिशत सूचनादाता कोविड-19 के बारे में जानते हैं। सर्वाधिक (96.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं को यह पता है कि कोविड-19 एक विषाणु जनित बीमारी है। सर्वाधिक (75.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं को इस बात की भी जानकारी है कि कोविड-19 कोरोना नामक वायरस से होता है। सर्वाधिक (96.00 प्रतिशत) सूचनादाता मास्क का प्रयोग करते हैं, जो नहीं करते हैं उनकी वजह घर से बाहर न जाना है। अधिकांशतः (52.00 प्रतिशत) सूचनादाता मास्क का प्रयोग दिन में करते हैं, जिनमें कुछ हमेशा, कुछ लोगों से मिलते समय तो कुछ बाजार में। अधिकांशतः (80.00 प्रतिशत) सूचनादाता शादी-विवाह आदि सार्वजनिक उत्सवों में मास्क का प्रयोग करते हैं। ऐसे अवसरों पर जो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं उसकी वजह चेहरा ढक जाना, सभी लोग नहीं लगाते इस लिए अथवा इच्छा का न होना पाया गया। अधिकांशतः (96.00 प्रतिशत) सूचनादाता हाथों को साबुन से धुलते हैं जबकि बाकी केवल सादा पानी से। अधिकांशतः सूचनादाता सेनेटाइजर का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः सूचनादाता आपस में में दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हैं।

अधिकांशतः (52.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं के कथनानुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक किया गया है। अधिकांशतः (84.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं के परिवार के सदस्य कोराना से संक्रमित नहीं थे। जो संक्रमित थे उन्होंने अपना इलाज डॉक्टर से करवाया। शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का दोनों टीका लगवा लिया है।

अधिकांशतः (80.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं का मानना है कि कोरोना एक बीमारी है जबकि कुछ का मानना है कि यह दैवीय प्रकोप है, कुछ का मानना है कि यह अफवाह है जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक मुद्दा भी मानते हैं।

अधिकांशतः (96.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं का मानना है कि कोविड-19 से सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है। अधिकांशत (76.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं के अनुसार कोविड-19 का प्रभाव कृषि पर पड़ा है जबकि कुछ का मानना है कि कोविड-19 का प्रभाव कृषि पर नहीं पड़ा है। जब सर्वेक्षित सम्भाग के सूचनादाताओं से पूछा गया कि कोरोना के कारण कृषि किस प्रकार प्रभावित हुई है तो उन्होंने निम्नलिखित प्रतिक्रिया व्यक्त की।

1. लागत अधिक लगी जबकि मुनाफा कम हुआ। 2. सब्जियाँ महँगी हो गयीं। 3. आनाज के दामों में गिरावट हो गयी। 4. महँगायी बढ़ गयी है। 5. किसान, मजदूर एवं फसल कटाई की मशीन दूसरे राज्य से नहीं आ पायी। 6. बीज की आपूर्ति नहीं हो पायी। 7. बाजार बन्द होने के कारण डीजल नहीं मिल पाने से। 8. खाद-पानी समय से नहीं मिल पाने के कारण। 9. फसल और सब्जियां किसान बेच नहीं पाये। 10. लॉकडाउन के समय किसान खेतों में नहीं जा सके जिससे फसल देख-रेख के अभाव में नष्ट हो गयी।

अधिकांशतः (92.00 प्रतिशत) सूचनादाताओं का मानना है कि कोरोना के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। जब अध्ययन समग्र के उत्तरदाताओं से पूछा गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस रूप में प्रभावित हुई है तो उनसे प्राप्त मिली जुली प्रतिक्रिया निम्नलिखित है।

1. दाल-सब्जी आदि सामान ऊँचे दाम पर मिल रहे हैं। 2. कोरोना के कारण कोई काम नहीं मिला, सभी साथी बेकार हो गये। 3. बेरोजगार होकर लोगों को घर लौटना पड़ा। 4. गांवों में काम-धंधा न होने से गरीबी बढ़ी है। 5. प्रवासी लोग अपने घरों को लौट आये, घर पर कोई काम न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हुई। 6. दुग्ध व्यापार ठप हो जाने से। 7. संयुक्त परिवारों में मुखिया के ऊपर बोझ बढ़ा है।

कोरोना के कहर का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण जन-जीवन पर पड़ा है। यद्यपि कि गाँवों में कोरोना का संक्रमण कम रहा और यदि हुआ भी तो शहरों की तुलना में मौतें कम हुईं। किन्तु इसका प्रभाव ग्रामीण कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा है जिसे निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है। ग्रामीण जनता ने इस प्राकृतिक चुनौती को स्वीकार किया और कृषि की दशा का सुधारने में लग गयी, किन्तु ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं आयी है।

शत प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। सूचनादाताओं के अनुसार सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम निम्नलिखित हैं।

- **मुफ्त राशन का वितरण।**
- **500 रूपये की अर्थिक सहायता।**
- **मनरेगा में काम मिला।**
- **ई-श्रम कार्ड के रूप में।**
- **प्रधानमंत्री सड़क योजना में काम देकर।**
- **ग्रामीण आवास योजना।**
- **जन-धन योजना।**
- **मुख्यमंत्री सुमंगला योजना।**

अध्ययन समग्र के अधिकांशतः (88.00 प्रतिशत) सूचनादाता सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से सन्तुष्ट दिखे। असन्तुष्ट सूचनादाताओं ने निम्नलिखित कारणों से असंतुष्टि व्यक्त की।

500 रूपये से काम नहीं चलता। राशन बहुत मुश्किल से मिलता है, अक्सर नाम कट जाता है। पक्षपात होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सूचनादाताओं द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये।

कृषकों को अधिक से अधिक मुनाफा प्रदान किया जाय। सभी को रोजगार एवं आवास प्रदान किया जाय। सभी को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान किया जाय। शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की जाय। फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाय। बेरोजगारी को दूर किया जाय। भूमिहीन किसानों को सार्वजनिक जमीन पर आवास प्रदान किया जाय। स्वच्छता अभियान चलाया जाय। हरित क्रान्ति को बढ़ावा दिया जाय। गाँवों में उद्योग-धंधे लगाये जाय। मनरेगा में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी बढ़ायी जाय।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि कोरोना के कहर का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण जन-जीवन पर पड़ा है। यद्यपि कि गाँवों में कोरोना का संक्रमण कम रहा और यदि हुआ भी तो शहरों की तुलना में मौतें कम हुईं। किन्तु इसका प्रभाव ग्रामीण कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा है जिसे निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है। ग्रामीण जनता ने इस प्राकृतिक चुनौती को स्वीकार किया और कृषि की दशा का सुधारने में लग गयी, किन्तु ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं आयी है। यद्यपि कि सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, ग्रामीण जनता द्वारा व्यक्त किया जाने वाला असन्तोष इस बात की ओर संकेत करता है कि सरकारी योजनाएँ नाकाफी हैं। इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सरकार का साथ दे। ❑

प्रो. अश्विनी महाजन

प्रोफेसर,
पीजीडीएवी कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

आत्मनिर्भरता में बचत की भूमिका

यूँ तो बचत एक वरदान है। बचत करते हुए हम न केवल अपने लिए संपत्ति और संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भलीभाँति कर सकते है, बल्कि बुरे दिनों के दौरान विपदा को भी कम कर सकते हैं। भारतीय परंपराओं, स्वभाव और संस्कारों में बचत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अक्सर हम अपने द्वारा संचित संसाधनों से अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाते हैं।

समाज में चाहे जो भी सोच, स्वभाव अथवा परंपरा रही हो, लेकिन भारत में कभी भी अलग प्रकार के विचार की अभिव्यक्ति पर रुकावट नहीं रही। हमारे ही वांग्मय में एक दार्शनिक 'चार्वाक' का उल्लेख आता है, जिन्होंने बचत संस्कृति के विपरीत एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम 'चार्वाक' सिद्धांत भी कह सकते हैं। उनका यह सिद्धांत भौतिकवादी विचार पर आधारित है। उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से कहा ''यावत् जीवेत सुखम् जीवेत। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। भस्मिभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत:।'' जिसका भावार्थ यह है कि जबतक जीएँ सुख से जीएँ। कोई भी मृत्यु से बचा नहीं, एक बार जब शरीर जल जाएगा तो वापिस नहीं आएगा। इसका अभिप्राय यह है कि बचत तो छोड़िए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए ऋण भी लें। चाहे चार्वाक ऋषि ने यह बात कही हो, लेकिन भारतीय समाज ने कभी भी इस सिद्धांत को अपनाया नहीं।

प्राचीन काल से ही धनाढ्य लोग स्वयं के उपभोग से बची अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में रखते थे। उस समय बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान नहीं होने के कारण वे अपनी बचत को स्वर्ण अथवा अन्य संपत्ति के रूप में रखते थे। चूंकि हमारा समाज कभी भी सरकार की सहायता पर निर्भर नहीं रहा, समाज अपने लिए आवश्यक सुविधाएँ स्वयं ही जुटाता रहा है। इसीलिए बुरे दिनों में आपदा से निपटने के लिए आश्वासन एवं बीमा हेतु स्वयं की बचत से बढ़कर कुछ नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारे पुरातन मंदिरों में भी धन-धान्य की भरमार रही है। कई मंदिरों में तो वह धन-धान्य अभी भी कम-अधिक मात्रा में मिलता ही है। दक्षिण भारत के केरल प्रांत में पऽनाभस्वामी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कई टन सोने के सिक्के एवं अन्य वस्तुएँ सुरक्षित हैं। मंदिर की ये परिसंपत्तियाँ कई शताब्दियों से लगातार संग्रहित की जाती रही हैं। पऽनाभस्वामी मंदिर अकेला ऐसा मंदिर नहीं है, जहां अपार धन संपत्ति एकत्र है, इसके अलावा कई और मंदिर भी हैं, जो हमारे समाज के समर्पण और धन-धान्य के प्रतीक माने जाते रहे हैं। भारतीय समाज में पुरातन काल से ही धन-धान्य से समर्थ लोग स्वयं को धन का न्यासी मानकर, अपने उपभोग से बचाकर धन का उपयोग सराय, शिक्षण संस्थान एवं अन्य सामाजिक सरोकार के लिए भी करते थे।

बैंकों एवं अन्य आधुनिक वित्त संस्थानों के अभाव में लोगों की बचत को एकत्र कर उत्पादन कार्यों में लगाने की तो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया उस समय नहीं होती थी। वर्तमान में जैसे धन हस्तांतरित करने में आधुनिक तंत्र का उपयोग होता है, उस समय धन हस्तांतरित करने में हुंडी का उपयोग काफी प्रचलित था। लोग स्वयं की बचत को अपने पास तो रखते ही थे, नगर-सेठ और व्यवसायियों को भी धन देकर उससे लाभ कमाया जाता था। बचत संस्कृति का ही प्रभाव था कि देश के लोग सूखा एवं अन्य विपदाओं के बावजूद काफी हद तक अप्रभावित रहते थे।

हमारे देश में विचारों की स्वतंत्रता तो सदैव ही रही है, जैसे पूर्व में चार्वाक ऋषि ने ऋण लेकर उपभोग करने हेतु बचत

संस्कृति से इतर विश्वास व्यक्त किया था, उसी प्रकार वर्तमान काल में कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बचत तो दूर, हमे उधार लेकर भी उपभोग बढ़ाना चाहिए। ऐसे में वे उदाहरण देते हैं कि कार, गृह एवं अन्य प्रकार के ऋणों के आधार पर ईएमआई देते हुए खरीद करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऋणों के आधार पर हम अपनी मांग में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है और ग्रोथ संभव होती है।

लेकिन आज भी बचत का है खास महत्व

आजादी से पूर्व विदेशी शासन के कारण, देश के लोगों द्वारा खासी मेहनत के बावजूद हमारा देश प्रगति नहीं कर पाया। यदि पिछली सदी के प्रथम पांच दशकों को देखा जाए तो पता चलता है कि हमारी राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर एक प्रतिशत से भी कम थी, जिसके कारण हमारी प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि दर शून्य ही रही। इसका कारण यह था कि अंग्रेजी शासन के दौरान हमारे देश में उद्योगों का ह्रास भी हुआ और किसानों के शोषण और उनके अधिकारों के हनन के कारण, कृषि में भी निवेश की प्रेरणा समाप्त हो गई थी। इसलिए देश के लोगों में बचत संस्कृति के बावजूद, निवेश के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण उसका सदुपयोग नहीं हो पाया।

लेकिन आजादी के बाद देश में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के विकास के कारण लोगों की बचत को हम बेहतर तरीके से एकत्र करने में सफल हो रहे हैं। उधर पूंजी बाजार में भी बचत के निवेश की पर्याप्त संभावनाएँ मिलती हैं। उसके बावजूद लोग अपनी बचत का उपयोग अचल संपत्ति निर्माण एवं सोना-चांदी की खरीद में भी करते हैं। आजादी के बाद जैसे-जैसे बचत एकत्रीकरण की सुविधाएं बढ़ी, कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बचत का योगदान बढ़ता गया। जहाँ 1950-51 में कुल घरेलू बचत जीडीपी का मात्र 8.6 प्रतिशत ही थी, 1960-61 में यह बढ़कर 11.2 प्रतिशत, 1970-71 में 14.2 प्रतिशत, 1980-81 में 18.5 प्रतिशत, 1990-91 में 22.8 प्रतिशत और 2004-05 में 32.4 प्रतिशत तक पहुँच गई। देश में अधिकतम बचत दर 2007-08 में 36.8 प्रतिशत थी। लेकिन उसके बाद बचत दर में गिरावट देखने को मिल रही है। और यह वर्ष 2017-18 में 32.07 प्रतिशत और 2019-20 में 31.38 प्रतिशत रही। इसका सीधा-सीधा प्रभाव देश में पूंजी निर्माण पर दिखाई देता है। 1950-51 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण जीडीपी का 8.4 प्रतिशत, 1960-61 में 14.0 प्रतिशत, 1970-71 में 15.1 प्रतिशत, 1980-81 में 19.9 प्रतिशत, 1990-91 में 26.0 प्रतिशत और 2007-08 में 38.1 प्रतिशत तक पहुँच गया था। उसके बाद बचत दर में कमी के कारण यह सकल घरेलू पूंजी निर्माण वर्ष 2017-18 में 33.89 प्रतिशत और वर्ष 2019-20 में 32.19 प्रतिशत पहुँच गया।

हमारे देश में विचारों की स्वतंत्रता तो सदैव ही रही है, जैसे पूर्व में चार्वाक ऋषि ने ऋण लेकर उपभोग करने हेतु बचत संस्कृति से इतर विश्वास व्यक्त किया था, उसी प्रकार वर्तमान काल में कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बचत तो दूर, हमे उधार लेकर भी उपभोग बढ़ाना चाहिए। ऐसे में वे उदाहरण देते हैं कि कार, गृह एवं अन्य प्रकार के ऋणों के आधार पर ईएमआई देते हुए खरीद करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऋणों के आधार पर हम अपनी मांग में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है और ग्रोथ संभव होती है।

बचत और पूंजी निर्माण की बढ़ती दरों ने देश में ग्रोथ की बेहतर स्थिति निर्माण की और जीडीपी की ग्रोथ की दर पूंजी निर्माण की दर के अनुपात में बढ़ती गई। 1950 से 1980 के तीन दशकों में हमारी राष्ट्रीय आय की ग्रोथ की दर मात्र 3.5 प्रतिशत ही थी, लेकिन 1980 से 1990 के दशक में यह 5.2 प्रतिशत थी, लेकिन 2001-02 से 2011-12 के बीच में यह 8 प्रतिशत तक पहुँच गई थी। समझा जा सकता है कि पूंजी निर्माण की बढ़ती दरों ने यह संभव कर दिखाया।

आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है घरेलू बचत

कुछ अर्थशास्त्री यह तर्क देते हैं कि पूंजी निर्माण तो विदेशी पूंजी से भी हो सकता है। विदेशी पूंजी से भी व्यवसाय खुल सकते हैं, रोजगार भी निर्माण हो सकता है और जीडीपी भी बढ़ सकती है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि विदेशी पूंजी पर निर्भरता से देश पर देनदारियां बढ़ती हैं और विदेशी मुद्रा भंडारों पर दबाव बढ़ता है। चाहे विदेशी यहाँ अंश पूंजी में भी निवेश करते हैं और देश पर उधार की देनदारियाँ नहीं बढ़ती, लेकिन विदेशी कंपनियाँ देश से भारी मात्रा में धन रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, डिविडेंड, लाभ एवं वेतन के रूप में अपने मूल देशों में ले जाती है। यह सभी विदेशी मुद्रा में जाता है। गौरतलब है कि आज भारत में जितना विदेशी निवेश आता है, उससे भी ज्यादा मात्रा में इन तरीकों से देश से विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। यही नहीं देश के संसाधनों पर विदेशियों का कब्जा बढ़ता जाता है। आज देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक घरेलू संसाधनों से निवेश को बढ़ाते हुए देश का विकास करें। नहीं भूलना चाहिए कि ब्राजील, अर्जेंटीना और लेटिन अमेरिका के अन्य देश ही नहीं श्रीलंका और कई अन्य देशों ने विदेशी पूंजी पर अधिक निर्भर होकर अपने-अपने देशों के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं।।❑

सबका साथ सबका विकास की अवधारणा

डॉ. ईश्वर चन्द्र शर्मा
सहायक आचार्य
(राजनीति विज्ञान)
राजकीय महाविद्यालय, रोहट
पाली (राज.)

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम् की घटक अवधारणा सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा हैं। इस अवधारणा के मूल तत्त्व प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं वेदों में निहित है। जिसका सार है समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास और इस हेतु सभी का समन्वित प्रयास। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी इस अवधारणा को अभिव्यक्ति दी है। कौटिल्य ने लिखा है –

प्रजा सुखे सुखः राज्ञः
प्रजानाञ्च हिते हितम् ।
नात्मप्रियं सुखं राज्ञः
प्रजानाञ्च सुखे सुखम्।।

अर्थात् ''प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है।'' कौटिल्य के अनुसार– ''ता पितेवा नुगृहीयात्।'' अर्थात् राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का सम्बन्ध होना चाहिए। यह इस बात को प्रकट करता है कि जिस प्रकार परिवार में पिता और पुत्र मिलकर परिवार के विकास में योगदान देते हैं, वेसे ही राजा और प्रजा को परस्पर समन्वय के साथ राज्य और उसके सभी नागरिकों के विकास में अपना योगदान देना चाहिए।

कौटिल्य ने राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य भी सौंपे हैं। इनके अन्तर्गत राजा दान देगा और अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन-पोषण की व्यवस्था करेगा। असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों का भरण-पोषण करेगा। जो किसान खेती न करके जमीन परती छोड़ देते हों, उनके पास से जमीन लेकर दूसरे किसानों को देगा। उसके अन्य कर्त्तव्य कृषि के लिए बान्ध बनाना, जलमार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना, दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना और उन्हें बीज देना है। आवश्यक होने पर उसे धनवानों पर अधिक कर लगाकर धन को गरीबों में बांट देना चाहिए। कौटिल्य द्वारा राजा के लोकहित और सामाजिक कल्याण सम्बन्धी बताए गए उपरोक्त कार्य सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा के मूल तत्वों की ओर संकेत करते हैं।

महात्मा गांधी के 'सर्वोदय' सम्बन्धी विचार हो या संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से सम्बन्धित बिन्दू, सभी सबका साथ सबका विकास के प्रेरक तत्त्व कहे जा सकते हैं।

सबका साथ, सबका विकास आह्वान करता है जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग के बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ लेकर चलने और सभी के विकास का। यह अवधारणा सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील रहते हुए समावेशी विकास पर बल देती है। इस अवधारणा का मूल आधार है 'मानवधिकार तथा न्याय'। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में ''एक समाज के रूप में हमें मानव अधिकारों के महत्त्व को समझने और आचरण में लाने की आवश्यकता है। ये ही सबका साथ, सबका विकास का आधार हैं।'' उनके अनुसार– संस्कृत की एक उक्ति है – 'न्यायमूलं स्वराज्यं स्यात्' अर्थात् स्वराज के मूल में न्याय होता है, जब न्याय की चर्चा होती है, तो मानव अधिकार का भाव उसमें पूरी तरह से समाहित रहता है। शोषित, पीड़ित और वंचित जनों की स्वतन्त्रता, शान्ति और उन्हें न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ये विशेष रूप से अनिवार्य हैं। सबका साथ-सबका विकास, हमारे संविधान की मूल भावना को प्रकट करता है। 26 नवम्बर 2021 को संविधान दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी भावना को प्रकट करते हुए कहा था कि ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति है।''

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनता है अत: सभी व्यक्तियों को अपने पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में ''आवश्यकता इस बात की हैं कि व्यक्ति अपने अंह का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य कर दे।'' यदि व्यक्ति ऐसा कर देता है, तो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पुष्ट होती नजर आऐगी। विवेकानन्द जी के अनुसार अतीत में भारत के राष्ट्रीय जीवन का निर्माण समाज सेवा तथा व्यक्ति की मुक्ति के आदर्शों की नींव पर किया गया था। इन श्रेष्ठ आदर्शों को पुन: प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना है। यदि ऐसा होता है, तो सबका साथ सबका

विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2020 को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया और लोगों से अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जुटे डाक्टर, मेडिकल स्टाफ, मीडिया कर्मियों को धन्यवाद अर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने धन्यवाद अर्पित करने हेतु कहा कि 22 मार्च की शाम ठीक 5 बजे अपने घर के दरवाजे पर खिड़की के पास या बालकनी में खड़े होकर 5 मिनट तक ताली बजाकर, थाली बजाकर इनके प्रति धन्यवाद अर्पित करे।

मोदी जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू की सफलता और समस्त देशवासियों द्वारा ताली-थाली बजाकर कोरोना वारियर्स का धन्यवाद ज्ञापन भी सबके साथ-सबके विकास की अवधारणा की अभिव्यक्ति करता है।

कोरोना महामारी के समय 3 अप्रैल 2020 को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से 5 अप्रैल 2020 को रात्रि नौ बजे नौ मिनट के लिए घर की लाइट बन्द करके एक दीया, मोमबत्ती या मोबाइल फ्लेश लाइट जलाने की अपील की। इस अपील का व्यापक प्रभाव पड़ा और सम्पूर्ण देशवासियों ने 5 अप्रैल को रात नौ बजे दीया जलाकर कोरोना महामारी से लड़ाई में सबके साथ का भरोसा दिलाया।

कोरोना काल में दानदाताओं द्वारा मुफ्त राशन एवं खाद्य सामग्रियों का वितरण, पलायन करते मजदुरों हेतु वाहन व्यवस्था, भंडारे, गंभीर मरीजों हेतु प्लाज्मा डोनेशन, दुकानों के किराये माफ करना आदि सभी के साथ द्वारा सभी के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के उदाहरण कहे जा सकते हैं।

कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पी एम केयर्स फंड बनाया गया था। इसमें सरकारी एवं निजी संस्थाओं ने बढ़चढ़कर दान दिया। 18 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों के मुफ्त टीकों की व्यवस्था और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों द्वारा सशुल्क टीके लगाया जाना भी सबका साथ-सबका विकास के उदाहरण कहे जा सकते हैं। कोरोना काल में कई जगह ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले जब कम गम्भीर रोगियों ने ज्यादा गम्भीर रोगियों हेतु स्वेच्छा से ऑक्सीजन अथवा रेमेडेसिविर इंजेक्शन का त्याग किया।

भारत में शुरू किया गया ई-श्रम पोर्टल सबका साथ-सबका विकास की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा सकता है। भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति विकट है। महामारी के दौरान और बदतर हो गई। इस दौरान पलायन करने वाले मजदूरों की दुर्दशा सामने आई। इसमें सुधार हेतु ई-श्रम पोर्टल उपयुक्त कदम है।

ई-श्रम कार्ड का यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर (यूएएन) देश भर में मान्य होगा। इसके आधार पर कार्डधारक को सामाजिक सुरक्षा, जैसे बीमा कवर, मातृत्व लाभ, पेंशन, शिक्षा, प्रोविडेंट फंड, आवास योजना आदि लाभ मिलेंगे। सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को अपनी पहचान संबंधी जानकारियाँ पोर्टल पर उपलब्ध करवानी होंगी, जैसे नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल आदि। साथ ही, ई-श्रम कार्ड के आधार पर प्रवासी मजदूर अपने बच्चों को निकटवर्ती स्कूल में प्रवेश दिलवा सकते हैं। यह उनकी मुख्य समस्याओं में से एक बड़ी है। ई-श्रम आइडी को वे पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाय) के अनुसार, लाभार्थियों की मृत्यु होने या स्थाई रूप से दिव्यांग होने की स्थिति में 2 लाख रूपए व आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 1 लाख रूपए की आर्थिक मदद का प्रावधान है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनता है अतः सभी व्यक्तियों को अपने पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में "आवश्यकता इस बात की हैं कि व्यक्ति अपने अंह का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य कर दे।" यदि व्यक्ति ऐसा कर देता है, तो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पुष्ट होती नजर आऐगी। विवेकानन्द जी के अनुसार अतीत में भारत के राष्ट्रीय जीवन का निर्माण समाज सेवा तथा व्यक्ति की मुक्ति के आदर्शों की नींव पर किया गया था। इन श्रेष्ठ आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पात्र कर्मी ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं निर्माण क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूर, गाड़ी व प्लैटफॉर्म मजदूर, ठेले-रेहड़ी वाले, घरेलू कर्मचारी, कृषि कर्मी, दूध वाले, मछुआरे, ट्रक चालक वगैरह। पात्र कर्मचारी चार लाख से भी अधिक साझा सेवा केंद्रों (सीएससीएस) के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। यह केंद्र डिजिटल सेवा आदायगी के केंद्र हैं। गत 30 दिसम्बर तक पोर्टल पर रजिस्टर करने वालों की संख्या 27 करोड़ पहुँच गई।

सबका साथ सबका विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि नक्सलियों के गढ़ रहे इलाके बस्तर में अब किसान खेती कर रहे हैं। बस्तर की जिस दरभा घाटी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल समेत 33 लोगों को नक्सलियों ने मार डाला था, वहीं से एक छोटी शुरूआत ने बस्तर को अलग दिशा दे दी है। महज 22 एकड़ से कॉफी की खेती की यहाँ शुरूआत हुई, जो अब पूरे बस्तर अंचल में 5000 एकड़ में होने जा रही है। इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन होना तय है। रायपुर और दिल्ली में बस्तर कैफे खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी साल अगस्त-सितंबर तक 750 एकड़ की फसल तैयार हो जाएगी। यहाँ सरकार ने कॉफी की खेती को बढ़ावा दिया है। 2018 से लेकर 2022 तक कॉफी की खेती में 22 हजार 264 लोगों को रोजगार मिला है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा प्राचीन भारतीय दर्शन का मूल है जिसकी क्रियान्विति वर्तमान में विभिन्न योजनाओं जैसे उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, पी एम आवस योजना, स्वच्छ जल मिशन योजना, पी एम किसान सम्मान निधि योजना, आदि योजनाओं के माध्यम से होती नजर आ रही है। हालांकि इसके मार्ग में बहुत सी बाधाएँ हैं, किन्तु आशा की जानी चाहिए कि हम इन बाधाओं को पार कर सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ❑

Sabaka Sath Sabaka Vikas

A Mission of Nation-building

Dr. Smita Raosaheb Deshmukh

Principal,
Matoshree Vimalabai
Deshmukh Mahavidyalaya,
Amravati (Maha.)

Prime Minister Narendra Modi on Sunday gave a call for Sabka Prayas' (everyone's efforts) along with 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas' for building a self-reliant India.The sudden emergence of the COVID-19 pandemic is causing a severe blow to state economies, businesses and workers. The pandemic is transforming how we think about our economies and our societies. The policy choices, governments make today will determine their success in building a Nation more inclusive and more resilient tomorrow. It is an opportunity to chart a path that empowers everyone to face the future with confidence. While the growth of a country is dependent on its economy, the real way to measure its achievement is to find out how successful its citizens are. Government of India is taking several steps to ensure that we are well prepared to face the challenges and threats posed by COVID-19. Everyone's efforts are very important in achieving all our goals and to bridge the gap between lives of children, youth, women, farmers in villages and cities.

The corona virus pandemic has wreaked havoc in everyone's life. There is no one in the world who has remained untouched by the effects of the virus. Some have lost their jobs;

some have lost their families and friends. One of the most important factors in the fight with the virus is to empower the citizens with accurate information and enable them to take precautions as per the advisories being issued by different Ministries. Children across the world have lost the school-going experience. However, it may not be all bad. After all, every cloud has a silver lining. Thus, COVID-19 has a positive impact on health, employment, and education as well.

"The nation needs to change and we need to change as citizens as well according to the changing times", PM. India.

"The world is facing an unprecedented test. And this is the moment of truth…The recovery from the COVID-19 crisis must lead to a different economy…. Everything we do during and after this crisis must be with a strong focus on building more equal, inclusive and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of pandemics, climate change, and the many other global challenges we face".

UN Secretary General Antonio Guterres.

The COVID-19 Inter-Ministerial Notifications website serves this purpose efficiently by providing COVID-19 related notifications from various Ministries in a format that is accessible, that is secure & scalable. India has faced the COVID-19 situation with fortitude and a spirit of self-reliance. The opportunity we have is to 're-imagine' a world that makes human beings safer today, as well as tomorrow. The world has an unprecedented opportunity to put in place the solutions that respond effectively to COVID-19 now, but that also strengthen the systems to better respond to future crises – whether they be pandemics or disasters. These are the opportunities that truly pay off in terms of recovery, job opportunities, and better conditions in schools and health care facilities.

Nation-building refers to the process of constructing or structuring a national identity using the power of the state. This process aims at the unification of the people within the state so that it remains socially, economically, educationally, politically stable and viable in the long run.

The clarion call given by the Honorable PM to use these trying times to become Atmanirbhar (self-reliant) has been very well received to enable the resurgence of the Indian economy. For Atmanirbhar Bharat we can focus on the Five pillars : Economy, Infrastructure, System, Vibrant Demography and Demand. We need to think about how we are addressing the ripple effects, such as the socio-economic impacts, as well as variety of other growing risks, such as climate change and environmental degradation, that are hampering our ability to respond to both the current and

future crises.

The term "Building Back Better" has been increasingly and widely used in the context of the economic recovery from COVID-19. The notion originated in the context of recovery and reconstruction from physical disasters with an emphasis on making preventative investments that improve resilience to, and so reduce the costs of, future disasters. The challenge of re-igniting the global economy in the aftermath of the economic crisis triggered by COVID-19 is of course different. Even at the global level, there is still an emphasis on prevention, as the investments and behavioral changes made will pay dividends in the future through reduced exposure and increased resilience to costly future disruptions – whether due to climate change, disease, or a confluence of these or other factors. A central dimension of 'building back better' is the need for a people-centred recovery that focuses on well-being, improves inclusiveness and reduces inequality.

To build back better for all generations, I think we should consider

Updating national youth strategies in collaboration with youth stakeholders to translate political commitment into actionable programmes.

Partnering with national statistical offices and research institutes to gather disaggregated evidence on the impact of the crisis by age group to track inequalities and inform decision-making (in addition to other identity factors such as sex, educational and socio-economical background, and employment status).

Providing targeted policies and services for the most vulnerable youth populations, including young people not in employment, education or training (NEETs); young migrants; homeless youth; and young women, adolescents and children facing increased risks of domestic violence.

The COVID-19 pandemic has disrupted every aspect of our lives. Even before the onset of the crisis, the social and economic integration of young people was an ongoing challenge. Now, unless urgent action is taken, young people are likely to suffer severe and long-lasting impacts from the pandemic. The youth of a nation are the backbone and the most powerful force within the nation. They are the hope of the future and can shape the destiny of a country.

Conclusion

The COVID-19 pandemic has disrupted every aspect of our lives. Even before the onset of the crisis, the social and economic integration of young people was an ongoing challenge. Now, unless urgent action is taken, young people are likely to suffer severe and long-lasting impacts from the pandemic. The youth of a nation are the backbone and the most powerful force within the nation. They are the hope of the future and can shape the destiny of a country. History shows that countries subjected to alien rule have without exception sought the help of youth in times of crisis. The youth have also been instrumental in the change of governments, whenever need for such a change has been felt. They have always been in the forefront in the building of political, social and economic orders of a society. They play a positive role for the cause of a nation and national integration. Today's generation faces greater challenges in national building due to the force and pressure of internal and external conflicts.The only solution to make the life of every citizen more meaningful, purposeful for development of nation is 'sabka sath sabaka vikas'. Only in this way will we be able to build a stronger and healthier post-pandemic economic and social system.❑

Impact of Vaccination on Economy

Dr. Babita Solanki

Assistant Professor,
Jawaharlal Nehru
T.T.college, Sakatpura,
Kota (Rajasthan)

Two years into the COVID-19 pandemic, the global economy continues to be plunged by uncertainty, with repeated waves of mutated variants, disruptions in supply-chain, and a return of inflation in both emerged and emerging economies. The focus of all world power was then focused to save the life of human beings, so this thing shifts the expenditure from less-important thing than human life to be on human life. Through this we saw a sharp decline in capital expenditure in the very first year of the pandemic. This pace downed the economies worldwide. In this context, it is important to evaluate the pace of growth revival in India as well as the strength of economic stability indicators. It is also essential to look at progress in vaccination as this is not just a health response but also a shot against economic disruptions caused by repeated waves of the pandemic.

All the sectors of economy have been impacted from this pandemic as well as vaccination drives, but here are four major sectors, under which we have seen the significant impact on the economy.

Hospitality Sector

The Improved vaccination drive has pushed Indian hospitality industry on an upward trajectory. Ease in travel restrictions has also parted its roles in growth of this particular sector. According to JLL, a management firm, the tourist footfall has seen a sharp rise after passing of the second wave. This helped the hospitality industry revive in V-shaped graph.

Passing of the Omicron (third) wave did not make any significant impact on growth of this sector. Although this wave slower down the pace but not completely, because vaccination has made a vital role to fight with the third wave. So the travel restrictions were eased as soon as the wave passed. The latter part of 2021 was the large-

ly the best performing period of the last year bolstered by long weekends, holidays during festivals, and social gatherings.

Also, in March 2022 witnessed a significant increase in international arrivals as compared to the same period previous year, and it is expected witness growth in airline and rail travel, which will, in turn, provide impetus to hotel performances.

The domestic segment will continue to drive demand for both corporate and leisure travel. As restrictions against social gatherings eased, the social Meetings, Conferences, and Exhibitions will improve to provide much-needed business to the industry going forward.

This immediate recovery would not have been possible without improved confidence in the minds of travellers due to the high vaccination rates achieved by the nation. The hospitality sector is likely to recover well in 2023 even as uncertainty around different Covid variants and waves continue.

Food and Agriculture business:

Food and agriculture products were marked essential by The Government of India for the pandemic. Means the supply of these goods must not be disrupted.

The impacts of COVID-19 on the farming sector and farm households can be at their highest at the beginning phase of the pandemic. Farm labor shortages, input shortages, machinery shortages, poor access to credit and consultancy, and movement restrictions were pronounced during the initial phase of the lockdown, indicating that there needs to be better preparedness in the initial phase to safeguard the sector from major setbacks. During the pandemic, inputs that were supplied through shops faced a shortage especially at the beginning of COVID-19 compared to locally available organic materials, indicating the need to ensure the adequate storage of inputs anticipating such a pandemic. In other words, steps are needed at the beginning phase in the event of information on the pandemic outbreak. Perishable crops as, rice, bananas, vegetables, coconuts, and flowers suffered maximum crop loss compared to pulses, groundnuts, cotton, and rubber, which could all be stored after harvest.

The thorough vaccination drive made sure a good comeback from the above setbacks farm industry has received during repeated lockdowns viz., scarcity of labor force, difficulty in hiring farm, disruptions in supply chain, proper marketing of products etc. We have seen the two different aspects of this thing. Demand of farm products has hiked worldwide from Indian end because of Ukraine Russia war. But supply has not seen that growth as expected because farmers are producing less perishable goods as they were feared of imposing lockdown. But this fear has now overcome because of proper vaccination drive in rural areas too.

Manufacturing sector

Impact of Covid-19 on manufacturing sector can be seen as, the IIP (Index for Industrial Production) had dropped down to -9.6% in financial year 2020-21. This shows how badly this sector could perform. Main reasons for decline were supply

chain disturbances, raw material shortage, capacity underutilization, labour shortage, weeker demand, liquidity crunch, special regulatory restrictions etc.

These are the key factors to run this specific sector. After rolling out the vaccination drive across the nation, IIP has seen the rise in its very first year of drive. IIP has been increased by 1.3% during the year 2021-22. This shows that all the obstacles in growth in manufacturing sector has now been overcome by vaccination rollout.

Finance Sector

Financial Markets across the world have seen the worst plunge in 2020 over the time after 1930 and 2008. These were caused because all the economic activities were on halt. Plunge in demand and supply made the economy weaker over the time led to dip in financial markets. Government of India also declared the moratorium for the more than 5 months to the borrowers of money. Moratorium provided relief to the borrowers but inflated the cost of borrowing to the lender. Also other measures were taken in the row to keep markets standing. But these were only the sheer solutions. To keep financial markets standing and running on full pace all the commercial activities must be ongoing.

Vaccines can help end recessions under the right circumstances. Enough people must be willing to get vaccinated to achieve herd immunity, and once that level is reached, businesses and consumers must return to prior levels of economic activity. Journey of vaccination has impacted on the economy positively uptill now. So we can say that these jabs are not only for human life but also for economy.

Vaccination drive and easing commercial activities have helped financial markets to grow significantly. Sensex has grown about 55% from its worst point dipped during first lockdown. Also Sensex has hit highest point of 60000 ever since started. This is showing vaccination positivity on the market, because growing index does not only show the current situation but also shows the future value of the company as well as economy.

Conclusion:

Vaccines can help end recessions under the right circumstances. Enough people must be willing to get vaccinated to achieve herd immunity, and once that level is reached, businesses and consumers must return to prior levels of economic activity. Journey of vaccination has impacted on the economy positively till now. So we can say that these jabs are not only for human life but also for economy. ❑

Shades of Economic Crises in Grip of Covid-19 Pandemic in India

Dr. Suneel Kumar

Associate Professor,
Department of Commerce,
Shaheed Bhagat Singh
College, University of Delhi

An invisible virus is shuddering the visible global economy as it continues to make giant distraction to life and livelihoods.The viral disease Covid-19 caused by SARSCoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) first appeared in the Hubei region of China in December 2019 ((Wang, Kaperak, Sato, & Sakuraba, 2021), spread rapidly around the world, and developed into a global pandemic. (Zhu et al.2020; Velavanet al.2020). The unidentified virus was termed the "Covid-19 virus" later on (Albaqawi, Pasay-An, Mostoles Jr, & Villareal, 2021). WHO has announced the Covid 19 episode as a global public health emergency (http://www.who.int/csr/don/12january2020novelcorona viruschina/en/). It has now been more than two years since the first outbreak, when WHO confirmed report of infections of unidentified viruses in Wuhan City, China, on December 31, 2019 (Andrews et al., 2020). Coronaviruses (CoV) are a diverse group of viruses that cause spectrum of symptoms ranging from the common cold to life-threatening diseases (Carbone, Lednicky, Xiao, Venditti, & Bucci, 2021; Nikolopoulou & Maltezou, 2021).

The economic impact of the Covid related restrictions has tremendously impacted the Indian economy. So when the coronavirus outbreak hit Indian shores in early 2020 (Bhatt & Kumar, 2021; Garg, Gupta, & Kumar, 2021), the Indian economy was already in a tailspin, with growth plummeting to an 11-year low of 3.1%in the March quarter of FY20. The rapidly rising number of Covid-19 incidents pushed the government to impose a nationwide lockdown, resulting in India's first recession in 40 years in FY21 (at -6.6 percent) (Dev & Sengupta, 2020; Mukhopadhyay & Demand, 2021). Although the economy was improving, the new wave, which started in March 2021, claimed many more deaths and slowed economic development significantly. According to high-frequency statistics, in striking comparison to the two previous coronavirus epidemics, the

Indian economy emerged from the Omicron wave in January with little damage. Yet, the continuous rise of Covid-19 cases is still alarming. The coronavirus epidemic has mostly disrupted economic activities and resulted in human life loss in India. Along with causing damage to the lives of human beings, Covid-19 has also affected many Indian industries (Mohanty & Mishra, 2021). Almost all industries (aviation, tourism, food, agriculture, telecommunications, pharmaceutical, oil & gas, and so on) (Bal & Mohanty, 2021; Debbarma & Durai, 2021; Kaushal & Srivastava, 2021; Pavan Kumar et al., 2021; Mittal & Sharma, 2021; Mohanty & Mishra, 2021) have withered as domestic demand and exports were hit, pushing economic crisis into a disaster. Navigating through the massive turn of challenges into meaningful change for the potential solutions is dire need of the hour.

1. Aviation & Tourism sector

Aviation and tourism, together, represent nearly 4 and 9.2 percent contribution to our GDP. About 43 million people got employment in the tourism industry in the financial year 2018-19. The pandemic drastically impacted the businesses of airlines and tourists. According to the common consensus, Covid will have a bigger effect on these firms than 9/11 and the 2008 Global Recession (Cho & Saki, 2021). Since the pandemic's emergence, these two businesses have been strangling significant challenges in cash flow. They face existential 38 million layoffs, which equates to seventy percent of the total employment. , Struggling with significant cash flow challenges, Jobs in both the white-collar and blue-collar sectors would be threatened since the pandemic emerged. According to IATO (Indian Association of Tour Operators) estimates, these businesses might lose up to 85 billion rupees as a result of travel bans (Pawan Kumar, 2021; S. Kumar, Kumar, & Attri; Suman & Kumar, 2021). The epidemic has also prompted a rush in technology sector. The hospitality sector is undergoing a replay of 2020, as various states have enforced lockdowns. Hotels, homestays, pubs, nightclubs, concerts, and other businesses are all part of the hospitality sector. Restriction and shut downs enforced by state governments have taken a huge toll on the industry, which accounts for a large chunk of India's yearly GDP. Tourism and aviation are tightly intertwined industries. During the initial shock, the sector that employs millions of Indians began to revive, but with reoccurrence of COVID-19 came to cause even more damage! The tourism industry accounts for more than 7% of India's yearly GDP. It includes hotels, homestays, lodges, and other sorts of amenities (Suman & Kumar, 2021). The second set of limitations has effectively destroyed the tourist industry, which was already fighting to recover from the initial loss sustained by enterprises in 2020.

The economic impact of the restrictions can be significant, straining global supply chains and the fragile economic recovery due to the extent of the damage caused, it is clear that the present recession is qualitatively different from earlier downturns and rising unemployment will cause havoc in the business environment. Adopting the novel approach as "move toward localization, cash conservation, supply chain resilience, and innovation" could assist entrepreneurs to outline a new course during current volatile environment. According to preliminary estimates, the Indian economy would grow by 9.2 percent in 2021-22 after contracting in 2020-21. This suggests that overall economic activity has risen above pre-pandemic levels.

2. Food & Agriculture

In spite of the fact that farming and agriculture are the backbones of the economy (Gugalia, 2021), the influence on core agricultural output and agro-input demand is predicted to be modest. Earlier some of the state governments, allowed for the free movement of essential goods and services (fruits, vegetables and dairy). Online food shopping platforms have been significantly impacted as a result of uncertain mobility constraints and the stoppage of logistical vehicles. In the medium term, the Finance Minister and RBI detailed initiatives that will assist the industry and its employees (Klinck, 2021).

3. Telecom Sector

Before the onset of Covid-19 crisis, there were major changes in the telecom business in India due to short-term pricing wars between telecom operators. Most important services and enterprises remained active during the outbreak owing to the adoption of 'work from home' due to constraints. The telecom sector engaged almost 4 million people accounting for around 6.5 percent of GDP until 2020 (Searchinger et al., 2019). There is 10 percent surge in telecom sector due to larger usage of broadband. Telecom companies, on the other hand, are preparing for a significant decline in new subscription purchases. As policy direction, the government can help businesses by lowering regulatory standards and giving a moratorium on spectrum spending that businesses can use to expand their infrastructure.

4. Pharmaceuticals sector

Since the occurrence of the Covid19 health crisis, the pharmaceutical business has grown, especially in India, the world's largest producer of generic drugs. Cultivated in India (by early 2020), it exported Hydroxychloroquine primarily to the United States, United Kingdom , Middle East and Canada with a market penetration of55 billion US dollars (Dutta, 2021; Janardhan & Krishna, 2021; LONG & BAD, 2020). As a result of the outbreak, raw material imported from China observed a recent hike. Generic drugs suffer most from industry dependence on imports, disrupted in supply chains management and related shortcomings. Meanwhile, pharmaceutical businesses are suffering due to restrictions on the export of key equipment, personal protective equipment (PPE) kits and pharmaceuticals to ensure and secure the sufficient amounts for the country. The growing demand of drugs, along with the difficulty in obtaining them, further complicates matters. Reduced financial limitations on pharma enterprises, cheaper taxation, and resolving workforce shortages may be distinguishing factors at this critical moment.

5. Oil and Gas sector

India's oil and gas industry is massive on a global scale; it is the world's third largest energy consumer, trailing only the China and USA (Sajid, Yu, &Rehman, 2022), accounting for 5.2 percent of global oil demand and consumption (Bathrinath et al., 2021). Exports and customer transport (both bulk and human) declined as vehicle and industrial production declined, and the slump in the country reduced demand for transport fuels (two-thirds of total demand in the oil and gas industry). At that time, despite falling oil prices, the government raised excise and excise taxes to compensate for revenue losses and road taxes. The government may consider introducing a law to stimulate demand.

Conclusion

The current crisis demands international attention to build a more resilient and sustainable future.The health emergency has been accompanied by an unusual financial collapse in which producers and consumers have fallen arbitrarily and equally, even as they are depressing one another in feedback cycles. The seriousness of this crisis was exacerbated by the fact that the Indian economy had been declining for over a decade before the epidemic. As a result, India's ability to deal with the epidemic has been considerably diminished since March 2020. The economic impact of the restrictions can be significant, straining global supply chains and the fragile economic recovery due to the extent of the damage caused, it is clear that the present recession is qualitatively different from earlier downturns and rising unemployment will cause havoc in the business environment. Adopting the novel approach as "move toward localization, cash conservation, supply chain resilience, and innovation" could assist entrepreneurs to outline a new course during current volatile environment. According to preliminary estimates, the Indian economy would grow by 9.2 percent in 2021-22 after contracting in 2020-21. This suggests that overall economic activity has risen above pre-pandemic levels. Retail inflation increased during the initial wave due to mobility limitations and supply interruptions. However, as the global economy is recovering and material prices have increased, wholesale/retail pricing has remained higher, putting pressure on the Reserve Bank of India (RBI) to adopt a more supportive stance to boost growth. The Covid-19 has rendered the economy defunct and different sectors should necessitate immediate international policy action to restore economy with strategic policies to meet the present exigencies.❑

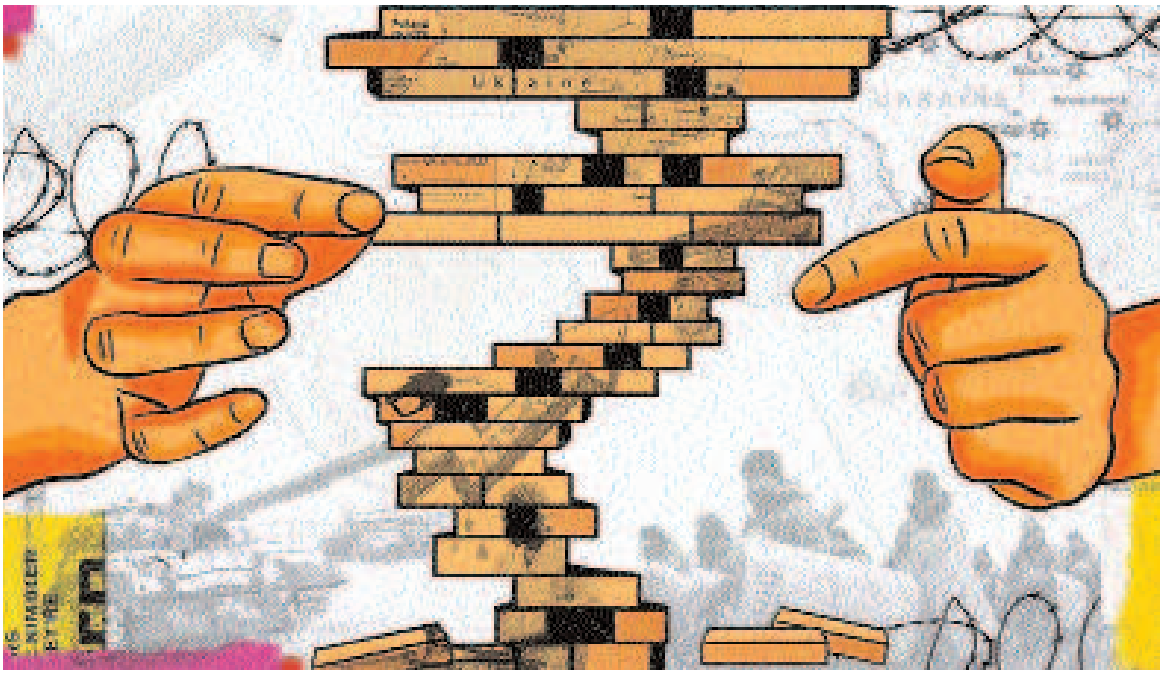

COVID-19 and Indian Economy : Aftermath and Future Outlook

Dr. Meenu Maheshwari

Associate Professor
Department of Commerce
and Management
University of Kota (Raj.)

The Indian economy has struggled over the last two years as a result of the COVID-19 pandemic. Infection outbreaks, supply-chain disruptions, and, more recently, inflation have made policymaking extremely difficult. These challenges faced by the Indian Government, therefore adopted The 'Barbell Strategy'(Nassim Nicholas Taleb) which incorporated a variety of safety nets to mitigate the impact on vulnerable sections of society and the business sector. It then pushed through a significant increase in infrastructure spending to restore medium-term demand, as well as aggressive implemented supply-side policies to position the economy for long-term expansion. This adaptable and multi-layered approach is based in part on a 'Agile framework'(Dean Leffingwell,2001) that employs feedback loops and real-time data monitoring.

Overall, macroeconomic stability indicators indicate that India's economy is well positioned to meet the challenges of 2022-23. The Indian economy's distinctive response strategy is one of the reasons for its success. Rather than commit to a strict reaction in advance, the Indian government chose to utilise safety nets for vulnerable groups on the one hand, while responding iteratively based on 'Bayesian-updating of information'(Pierre-Simon Laplace, 1974) on the other.

Another aspect of India's reaction has been a focus on supply-side changes rather than a complete dependence on demand management. These supply-side changes include deregulation of a variety of industries, process simplification, and the elimination of regulatory issues such as the "retrospective tax," privatization, and output incentives, among others. Even the government's substantial rise in capital spending, which generates infrastructural

capacity for future growth, can be considered as a demand and supply increasing reaction.

In India's supply-side strategy, there are two recurring themes:

1. Reforms that promote flexibility and innovation are needed to deal with the long-term unpredictability of the post-COVID environment. This includes factor market reforms, deregulation of sectors like space, drones, geospatial mapping, and trade finance factoring, process reforms in government procurement and the telecommunications sector, the elimination of legacy issues like retrospective tax, privatization, and monetization, and the construction of physical infrastructure.

2. Reforms aimed at making the Indian economy more resilient. Environmental policy, social infrastructure such as public tap water, toilets, basic housing, insurance for the poor, and assistance for vital businesses under 'Atmanirbhar Bharat'(Indian government on 13th may,2020) , and a strong emphasis on reciprocity in foreign trade agreements are just a few examples

Government makes easier their processes for activities where the government acts as a facilitator or regulator in "Process Reforms.".

The government ensures that the overall economy in general and MSMEs in specifically, will have access to financial aid. According to Dev and Sengupta(2020) the government during last year has used a variety of eighty High Frequency Indicators (HFIs) from both public and private sources to measure the underlying state of the economy in real time. These HFIs represent business, sevices, future outlook, macro-stability indicators, and a variety of other activities. Instead of depending on pre-defined responses from a 'waterfall framework'(Winston w. Royce,1970) , which has been the traditional way for defining policy in India and most of the entire globe, these HFIs enable policymakers in adapting their reaction to a dynamic circumstance.

Position of Indian economy after COVID-19 in every sector-

Overall, macroeconomic stability indicators indicate that India's economy is well positioned to meet the challenges of 2022-23. The Indian economy's distinctive response strategy is one of the reasons for its success. Rather than commit to a strict reaction in advance, the Indian government chose to utilise safety nets for vulnerable groups on the one hand, while responding iteratively based on 'Bayesian-updating of information'(Pierre-Simon Laplace, 1974) on the other.

According to the Economic Survey Report 2021-22, which is briefly described here :

1. According to World Bank, Asian Development Bank, and IMF predictions, India will continue to be the world's quickest expanding major economy in 2021-22.

2. In real terms, India's GDP to increase by 9.2% in 2021-22. India's GDP is expected to rise by 8.0-8.5% in 2022-23, thanks to broad vaccine coverage, benefits from supply-side changes and regulatory relaxation, healthy export growth, and the availability of fiscal headroom to increase capital spending.

India's growth forecast for 2022-23 is based on the assumption that there will be no further disease outbreak related economic disruption, that the monsoon will be normal and that oil prices will be in the US$70-$75/bbl range. Smt Nirmala Sitharaman, Union Minister for Finance and Corporate Affairs, states in pre -budget Economic Survey 2021-22 that the year ahead seems to be well set for a pick-up in private sector investment.

3. The pandemic has had the least influence on agriculture and associated industries, which is predicted to rise by 3.9 percent in 2021-22, as compared to 3.6 percent the previous year. In 2021-22, the central pool's acquisition of food grains continued to rise, accompanied by minimum support prices, which indicates well for national food security and farmer incomes.

The sector's good success was aided by government policies that assured regular seed and fertilizer deliveries despite pandemic-related interruptions.

4. After contracting by 8.4% last year, the service sector growth rate is 8.2% in 2021-22. The epidemic has struck this industry the hardest, especially those that involve human interaction. Travel, trade, and hotels, on the other hand, have yet to fully recover. Even while tourism earnings have dropped substantially, software and IT-enabled services exports have soared.

5. From a contraction of 7% in 2020-21 to an expansion of 11.8 percent in 2021-22, the industrial sector has made a strong comeback. The manufacturing, construction, and mining sub-sectors all had a similar fluctuation, however the utilities sector saw a more subdued cycle, as basic supplies like electricity and water were maintained even throughout the national lockdown.

6. India's balance of payments has remained in excess for the past two years, despite the global epidemic. The Reserve Bank of India was able to continue building forex reserves, which were valued at US$634 billion on December 31, 2021. This is more than the country's external debt and equals 13.2 months of imports.

India's merchandise exports reached a new high of $418 billion in 2021-22, surpassing the government's objective by around 5% and increasing by 40% over the previous year. India's merchandise imports totaled USD 495.83 billion - up 62.68 percent from USD 304.79 billion in 2020-21 (April-January) and 22.3 percent from 2019-20 (March-April). India's exports of products and services have been extremely strong thus far this year.

7. As per the Economic Survey, investment, as evaluated by Gross Fixed Capital Formation (GFCF) , is predicted to expand by 15% in 2021-22, bringing it back to pre-pandemic levels. The government's focus on accelerating the virtuous cycle of growth through capex and infrastructure spending has boosted capital creation in the economy, bringing the investment-to-GDP ratio to over 29.6% in 2021-22, which is greatest in seven years.

8. In both industrialized and emerging economies, inflation has resurfaced as a global issue. The composite consumer price index (CPI) inflation rate of 5.6 percent in December 2021 is well within the specified tolerance band fiscal deficit of 46.2 percent of budget estimates for April to November 2021. The lowering of food inflation led to a decrease in retail inflation in 2021-22. WPI (Wholesale Price Inflation) has been in double digits.

9. Despite the pandemic, the capital market explodes, with over Rs 89 thousand crore raised through 75 initial public offerings (IPOs) between April and November 2021, far more than in any previous year.

10. Despite facing the brunt of COVID-19 the Education system of India managed to cope up with the changing environment and turned its challenges into opportunities. The post pandemic era has transformed the face of education from conventional to the modern system. The gates have been opened for the digital learning through webinars, e- workshops, e- conferences, virtual meetings and teleconferencing. The educationists, academicians and learners got literate in context of digital technology which has led to expansion of digital literacy around the prevailed system. Digitalization in education has enhanced the worldwide exposure of the educators and learners as it has paved the way for easy access to e- learning material and interactions with experts around the world virtually.

11. Similarly, healthcare sector has also experienced boom in context of investments in various medical aids comprising of medical devices, pharmaceuticals, e-consultations, e-deliveries, use of technology and research and development. In the same line, automotive industry is likely to experience an upward surge and expansion by 2026.

Finally, overall macro-economic stability indicators imply that the Indian economy is well positioned to meet the difficulties of 2022-23, and one of the reasons for this is the Indian economy's distinctive response plan.❑